बंगाल : साम्प्रदायिक हिंसा की प्रयोगशाला

सुहरावर्दी से ममता तक

सम्पादकीय सलाहकार

प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक मंडल

डॉ. अलोक शर्मा, डॉ. गीता भट्ट

और

अनन्या सन्याल

शोध सहयोग

वैशाली राज, प्रीती कालरा, भानू कुमार

सम्पादकीय सहयोग

शिव कुमार सिंह

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

प्रकाशक
भारत नीति प्रतिष्ठान
नई दिल्ली- 110016
Email: indiapolicy@gmail.com
Website: www.indiapolicyfoundation.org

© India Policy Foundation

संस्करण
प्रथम, मार्च 2017

ISBN: 978-93-84835-22-4

मूल्य: 80/-

Designed by
SBM DIGITECH

प्राक्कथन

साम्प्रदायिकता की प्रयोगशाला

बहुत पुरानी बात नहीं है जब बंगाल भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलनों आदि में अग्रणी भूमिका में था। इस प्रान्त के बुद्धिजीवियों एवं राजनेताओं की सभ्यताई समझ और सांस्कृतिक चेतना ने भारतवर्ष को सदैव नूतनता प्रदान करने का काम किया। इसीलिए तो 18वीं-19वीं शताब्दी एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रयोगशाला बना गया था। इस उपक्रम में अनगिनत नाम जुड़े हुए हैं। राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चन्द्र पाल, सुभाष चन्द्र बोस, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जैसे लोग उन अनगिनत समाज सुधारकों, राजनेताओं, सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पुरुषों में कुछ नाम हैं जिन्होंने भारत के इतिहास पर स्वर्णिम छाप छोड़ी है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और राजनीतिक परिस्थिति क्या है? क्या यह प्रान्त राजा राममोहन रॉय, विवेकानन्द, टैगोर, बंकिम, बिपिन चन्द्र पाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामाजिक दर्शन और राजनीतिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? आधुनिककाल के इतिहास पर गौर करते ही पतन के कारण और परिणाम सामने आ जाते हैं।

साम्राज्यवादी शासक बंगाल की फौलादी एकता, सांस्कृतिक-आध्यात्मिक ताकत और राजनीतिक चेतना को ध्वस्त करना साम्राज्यवाद की स्थिरता के लिए आवश्यक मानते थे। लॉर्ड कर्ज़न ने सन् 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय का जोखिम उठाया। यह कदम शून्य में नहीं था। इसके पीछे साम्राज्यवादी विचारकों ने कठोर परिश्रम किया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हंटर कमेटी का सन् 1870 में गठन था। औपनिवेशिक शासकों ने विलियम विलसन हंटर (जो तत्कालीन इंडियन सिविल सर्विसेज का अधिकारी था) को मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के कारणों को तलाशने का काम सौंपा था। मात्र 4 हफ्तों में हंटर ने एक रिपोर्ट सौंपी जो 'भारतीय मुसलमान' के नाम से सन् 1871 में प्रकाशित हुई। उसने धूर्तता से यह स्थापित किया कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण बंगाली हिन्दू हैं। उसने शासकों को सुझाया कि मुसलमानों की साम्प्रदायिक आकांक्षाओं को सम्बोधित करें। उसी समय एक विचित्र विरोधाभास उजागर हुआ जो साम्राज्यवाद के कुटिल चरित्र को उजागर करता है। विभिन्न प्रान्तों के शिक्षा (Public Instruction) के निदेशकों, जिनमें उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रान्त (NWFP) भी शामिल था, ने मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण उनका आधुनिक शिक्षा से दूर रहना बताया और सरकार को सुझाया कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। परन्तु साम्राज्यवादी सरकार के मस्तिष्क में हंटर रिपोर्ट जगह बना चुकी थी। सरकार ने मदरसा शिक्षा को प्राथमिकता देना शुरू किया। प्रान्त की सांस्कृतिक एकता को साम्प्रदायिकता की लौ में विखंडित करने के लिए यह बीजारोपण किया गया था। कर्ज़न का बंगाल विभाजन का प्रयास उसी का विस्तार था।

एच.एस. सुहरावदी

साम्प्रदायिक विष के पौधे को खाद-पानी दिया जाता रहा। सामान्य हिन्दू उसकी उपेक्षा करता रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम कट्टरता को अल्पसंख्यक आधारों के नाम पर वैधानिकता देती रही। इसका आभास तब हुआ जब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। सन् 1946 में बंगाल में हिन्दुओं को भारी जान-माल की क्षति भुगतनी पड़ी थी। यह मुस्लिम लीग के एच. एस. सुहरावर्दी का शासनकाल था। वह संयुक्त बंगाल का प्रधानमंत्री (अप्रैल, 1946 से अगस्त, 1947 तक) रहा। जब मोहम्मद

ममता बनर्जी

अली जिन्ना ने पाकिस्तान के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई (Direct Action) की घोषणा की तब 16 अगस्त, 1946 और उसके आगे चार दिनों तक हिन्दुओं पर भारी हिंसक आघात हुआ। हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी को सुहरावर्दी ने किस हद तक संरक्षण दिया वह इसी बात से दिखाई पड़ता है कि उसने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया और पुलिस को शहर से हटा लिया। हाउस आफ कॉमन्स् में प्रस्तुत तथ्य के अनुसार, उन चार दिनों में 5,016 लोगों की हत्या हुई। वास्तव में यह आंकड़ा इससे कई गुना अधिक था। इसके बाद अक्टूबर, 1946 में नोवाखाली में दंगा हुआ। यह बंगाल के हिन्दुओं के लिए मात्र हिंसा का आघात नहीं था। यह उनके लिए एक सदमा था। बंगाल की स्वर्णिम विरासत पर हमला था। आजादी के बाद उससे सीखने की आवश्यकता थी। बंगाल के लिए अपनी स्वर्णिम विरासत के पुनर्जागृति करने का नया अवसर था। परन्तु ऐसा नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल साम्प्रदायिकता की प्रयोगशाला बनी रही। दृष्टिहीन राजनीतिक नेतृत्व ने साहित्य, संस्कृति, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में बंगाल की क्षमता की उपेक्षा की। बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता गया। तीन दशक के मार्क्सवादी शासन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम किया। ऐसा करने पर उन्होंने थोड़ी भी शर्मिंदगी या अपराध बोध का अनुभव नहीं किया। जब बंगाल को अपनी बदहाली का आभास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकल्प के रूप में ममता बनर्जी उभरीं। राष्ट्रीय पार्टियों की चूक ने ममता बनर्जी को मार्क्सवादियों के सामने एकमात्र विकल्प बना दिया।

ममता बनर्जी ने सुहरावर्दी को अपना आदर्श माना। प्रान्त में साम्प्रदायिक ताकतों को जिस कदर शह, समर्थन और संरक्षण दिया वह स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। पश्चिम बंगाल में द्वैध शासन है। दो मुख्यमंत्री कार्यरत हैं। एक रायटर्स बिल्डिंग में बैठती हैं- ममता बनर्जी तो दूसरा कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद में निवास करता है- मौलाना नुरुर रहमान बरकती। वह फतवा जारी करता है और ममता उसे राजकीय सम्मान देती है। यह लोकतंत्र, पंथनिरेपक्षता एवं संविधान का उपहास नहीं तो और क्या है जब ममता तसलीमा नसरीन (बांग्लादेशी साहित्यकार) की हत्या का फतवा जारी करने वाले बरकती के साथ एक मंच पर विराजमान रहती है?

प्रान्त के साम्प्रदायिक उपद्रवियों के प्रति पुलिस का रवैया सहानुभूति का है। जिन जिलों में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं वहां वे भय, आतंक और जुल्म के माहौल में जी रहे हैं। वे अपनी पूजा-पाठ के अधिकारों से भी वंचित किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल में सुहरावर्दी का पुनर्जन्म हो गया है। बंगाल में लगातार मिनी डायरेक्ट एक्शन (लघु प्रत्यक्ष कार्रवाई) हो रहे हैं। उनकी रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है।

फ्रांसिस रॉविंसन ने औपनिवेशिक शासकों के बारे में जो लिखा है वही रवैया ममता बनर्जी का है। "जहां तक मुस्लिमों की बात है उनके लिए राजनीति पहले है और प्रशासनिक नीति दूसरे पायदान पर। इसका दूरगामी बुरा परिणाम निकलेगा।"

बंगाल को पुनः जागृत होने में इतनी देर नहीं करनी होगी जितनी कर्ज़न काल के बाद मार्क्सवादियों के दौर में हुई थी। बंगाल को अपनी अस्मिता और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और साहित्य, सभ्यताई दृष्टि और आध्यात्मिक चेतना सबको सामने रखकर परिस्थितियों को बदलने के लिए एक मानसिक और साहसिक राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजरना होगा और उस प्रसिद्ध कहावत को पुनः चरितार्थ करना होगा कि 'बंगाल जो आज सोचता है भारत कल सोचता है।'

भारत नीति प्रतिष्ठान ने 'समकालीन पश्चिम बंगाल की तस्वीर कैसी है?' इस पर एक हस्तक्षेप पत्र प्रकाशित किया है जिसमें सभी आयामों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। यह पश्चिम बंगाल पर प्रतिष्ठान का दूसरा हस्तक्षेप पत्र है।

10 मार्च, 2017 **-- प्रो. राकेश सिन्हा**

पश्चिम बंगाल : तब और अब

बंगाल का इतिहास 4000 वर्ष पुराना है। गंगा के किनारे से ब्रह्मपुत्र तक पहुंची बंगाल की सीमा सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नजरिए से समुद्री तटों के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल भारत पहुंचने के लिए तटीय रास्ता है।[1] जिसे भारत का पूर्वी प्रदेश द्वार भी कहा जाता है। हालांकि इसका लाभ बंगाल को हमेशा मिलता रहा है। बंगाल को समुद्री रास्तों की वजह से व्यापारिक लाभ भी हुए हैं। जो बंगाल से सिल्क तट तक जुड़ा हुआ है।

बंगाल में ब्रिटिश आक्रमण

बंगाल को एक ओर समुद्री तट का व्यापारिक लाभ मिल रहा था; वहीं समुद्री तट से जुड़े रहने के कारण बंगाल ब्रिटिशों के लिए प्रवेश द्वार भी था जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। उर्वर, समृद्ध भूमि और कमजोर शासन का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया। जून, 1757 में प्लासी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली, हालांकि अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो अंग्रेजो का शासन भारत में 200 वर्ष पुराना था। अंग्रेजों का शासन समय के साथ-साथ बंगाल में मजबूत होने लगा और दिल्ली से मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय संस्कृति और राजनीति का केन्द्र बंगाल स्थापित हो गया।[2] बंगाल ने वर्ष 1776 तथा 1943 में भीषण अकालों का सामना किया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए बंगाल ने सन् 1905 तथा 1947 में दो विभाजन देखे। बंगाल ने वर्ष 1905, 1947 और 1971 में माइग्रेशन या कहें विस्थापनों का सामना किया। अंग्रेजों के बंगाल में आने से इसका प्रभाव बंगाल की सभ्यता और संस्कृति पर पड़ा, जिसकी वजह से बंगाल को कई लाभ भी हुए। जिसमें विज्ञान और साहित्यिक विकास के आधुनिक तरीके प्रमुख हैं।

बंगाल का पुनर्जागरण

19वीं और 20वीं सदी में बंगाल का पुनर्जागरण हुआ जिसमें कई महान हस्तियों का उद्गम हुआ[3] जिसने बंगाल को विश्वभर में प्रसिद्धि दिलाई। जिसके बाद बंगाल में छात्रों को अधिक प्रोत्साहित किया गया और जाति के भेदभाव की निंदा की गई। साथ ही बंगाल को विज्ञान और साहित्य की पहचान मिली। राजा राममोहन रॉय को "आधुनिक भारत के जनक" के रूप में जाना जाता है। जिन्होंने भारत को एक नई दिशा प्रदान की, वहीं बंगाल के ही पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द, जगदीशचन्द्र बोस, सत्येन्द्रनाथ बोस, बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल की संस्कृति और प्रगति का चेहरा बने जिन्होंने बंगाल के साथ-साथ पूरे राष्ट्र का उत्थान किया। ये उन हस्तियों के नाम हैं जिनकी जड़ बंगाल से जुड़ी हैं, लेकिन कार्य देश-विदेश तक प्रसिद्ध हैं।

1. Krishanu Dutta, "History of Bengal: From Stone Age to Trinamool Congress", India Today, May 20, 2016, http://indiatoday.intoday.in/education/story/history-of-bengal/1/673092.html (Accessed Feb. 2, 2017).
2. ibid.
3. Subrata Dasgupta, *"Awakening: The Story of the Bengal Renaissance"*, August 1 2011, p. 501.(Accessed Feb. 6, 2017).

रबिन्द्रनाथ टैगोर

राजा राममोहन रॉय

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय

स्वामी विवेकानन्द

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

बंगाल का विभाजन

बंगाल जिस अवधि के दौरान 1,89,000 वर्ग मील में फैला हुआ था उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू किया। उसी दौरान लॉर्ड कर्ज़न ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन कर एक चतुर राजनैतिक कदम उठाया, जिससे अंग्रेजों के लिए बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना आसान हो गया। अक्टूबर, 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप बंगाल में बड़े राजनैतिक संकट का जन्म हुआ। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम प्रारंभिक विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद विभाजन के प्रति अधिक ग्रहणशील बन गए और उन्होंने विभिन्न धार्मिक संगठनों की स्थापना की।

बंगाली हिन्दू, जिन्होंने बंगाल के व्यापार और ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत बनाया था, उन्होंने शिकायत की कि बंगाल का विभाजन उन्हें अपने राज्य में अल्पसंख्यक बना देगा। जिसके बाद स्वदेशी आंदोलन ने सफल विभाजन-विरोधी आंदोलन का प्रचार किया। इस आंदोलन के मुख्य निर्देशक (कर्ताधर्ता) अरविन्दो घोष, लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपत राय थे। साथ ही वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई भी इस आंदोलन में शामिल थे। इस आंदोलन से जहां एक ओर बंगालियों की बंगाली भावनाओं को संतोष मिला वहीं दूसरी ओर बंगाली मुसलमानों के लिए यह असंतोष का कारण बना।[4]

बंगाल हमेशा से भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए जिस समय बंगाल में विभाजन हो रहा था उसका प्रभाव सीधे इसके राजनीति पर पड़ा जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। राज्य के एकीकरण के बाद पूर्वी बंगालियों को असंतुष्ट छोड़ दिया गया, जिसने बंगाली मुसलमानों के बीच एक मजबूत राजनीतिक दूरदर्शिता को जन्म दिया। फलस्वरूप 1947 में धार्मिक मताग्रहों के साथ बंगाल का विभाजन हो गया। भारत विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाने लगा, हालांकि 1971 में पश्चिम पाकिस्तान के साथ आजादी के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना।[5]

स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा दिया और राष्ट्र को प्रेरित किया। जब भी इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र होता है बंगाल का नाम जरूर शामिल किया जाता है। बंगाल वह भूमि है जिसने राष्ट्र को बलिदान, समाज और संस्कृति के विद्रूपों के विरूद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित किया। साथ ही युवाओं को बौद्धिक शक्ति से लड़ने के लिए शिक्षा दी। बंगाल ने ही भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत प्रदान किया। अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसी क्रांतिकारी इकाइयों ने बंगाल के युवाओं को एकजुट कर विदेशी शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। विदेशी शासकों के विरुद्ध भारतीय विचारधाराओं को जन-जन तक फैलाने के लिए लेखकों, वक्ताओं और बंगाली बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसमें राजेन्द्र बसु, सुभाषचन्द्र बोस, चितरंजन दास, विपिनचन्द्र पाल, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, प्रफुल्ल चाकी, जतिन्द्रनाथ मुखर्जी, खुदीराम बोस, सरोजनी नायडू, अरविन्दो घोष, रासबिहारी बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं।

4. L. M. Bhole, "Essays on Gandhian Socio-Economic Thought", Shipra Publications, Delhi, 2000, (Accessed Feb.2017).
5. Thomas, Weber, "Gandhi, Deep Ecology, Peace Research and Buddhist Economics". Journal of Peace Research. 36 (3): 349–361, May 1999. doi:10.1177/002234339903600307. (Accessed Feb. 21, 2017).

अरबिन्दो घोष

सुभाषचन्द्र बोस

श्यामा प्रसाद मुखर्जी

बिपिन चन्द्र पाल

स्वतंत्रता के बाद बंगाल

स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक जिम्मेदारी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र पर अधिक केन्द्रित हो गई, लेकिन तथ्य यह है कि 1947 और 1971 के दौरान बंगाल को एक के बाद एक विभाजन और विस्थापन का सामना करना पड़ा जिसने प्रशासनिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। बांग्लादेश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसने युवाओं को काफी प्रभावित किया जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सन् 1970-71 में राज्य ने नक्सली आंदोलन के रूप में आतंकवादी क्रांति देखी।[6] बाद में बंगाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा शासित हुआ। पश्चिम बंगाल लगभग तीन दशकों तक भारतीय स्टालिनवादियों का कैदी बना रहा जिन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सामाजिक-आर्थिक विकास को दबाने एवं आतंक को बढ़ावा देने के लिए दमनकारी साधनों का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लिए कुछ कार्य किए। जैसे उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। जिसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला। इसकी वजह से वर्ष 2011 में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। एक आशा के साथ वर्ष 2016 के चुनाव में पुन: तृणमूल कांग्रेस को चुना गया। यद्यपि ममता बनर्जी द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए, उनसे जनता निराश थी। क्योंकि उनके इस शासनकाल में सत्तावाद और साम्प्रदायिकता का इस्तेमाल किया गया जो केवल कानून बनाने के काम आती रही, लेकिन कारगर आदेश नहीं दिए गए। उदाहरण स्वरूप पुलिस है, लेकिन प्रशासन नहीं। फलस्वरूप उनकी साम्प्रदायिक राजनीति ने राज्य में अत्याचार को जन्म दिया।[7]

6. Krishanu Dutta, "History of Bengal: From Stone Age to Trinamool Congress", India Today, May 20, 2016, http://indiatoday.intoday.in/education/story/history-of-bengal/1/673092.html. (Accessed Feb. 2, 2017).
7. Krishanu Dutta, "History of Bengal: From Stone Age to Trinamool Congress", India Today, May 20, 2016, http://indiatoday.intoday.in/education/story/his-to¬ry-of-bengal/1/673092.html. (Accessed Feb. 2, 2017).

बंगाल की वर्तमान स्थिति

वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की स्थिति निराशाजनक है। विश्व सभ्यता के इतिहास में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी विचारधारा के समाज को देखता या समझता है तो समाज की विचारधारा उन्हें जल्द ही अपनी चपेट में ले लेती है। इसी वजह से ममता बनर्जी का चुनावी एजेंडा काम नहीं आया क्योंकि जनता को समय के साथ यह अहसास होने लगा कि अशिक्षित नेता केवल लोकतंत्र के लिए बोझ हैं। साथ ही ममता बनर्जी की छवि खराब हुई क्योंकि जिस विचारधारा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी वह शासनकाल के दौरान कहीं नहीं दिखाई दी। ममता बनर्जी के 6 वर्ष के शासनकाल में यह देखा गया कि उनके अशिक्षित मंत्री निरंकुश हो गए। राज्य में अनियंत्रित साम्प्रदायिक हिंसा एवं हिन्दुओं को अपने घरों से दूर कर आपसी नकारात्मक विचारधाराओं का निर्माण किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल निरुद्देश्य और पक्षपाती दृष्टिकोण के लिए पहचान बना चुका है। ममता ने राज्य को शासित करने के अपने सबसे महत्वपूर्ण और स्थाई कार्य की उपेक्षा की है। इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यक और साम्प्रदायिक सीमाओं को लांघ दिया है।

ममता बनर्जी, एच. एस. सुहरावर्दी के नक्शे कदम पर चल रही हैं जिसने समाज का ध्रुवीकरण किया था। मार्क्सवादियों और ममता शासन ने बंगाल की परम्परागत छवि को क्षति पहुंचाई है और नकारात्मक छवि तैयार की है। परिणामस्वरूप भारत की पुनर्जागरण राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला बंगाल 'भ्रष्ट साम्प्रदायिक राज्य' के रूप में सामने आया है।[8]

निरंकुश और सबकुछ अपने नियंत्रण में रखने वाले स्वभाव की नेता ममता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.एम.) की दमनकारी नीति का पालन करके लोकतंत्र को धोखा दिया और विभिन्न 'षड्यंत्र सिद्धांतों' को जन्म दिया है। हाल ही में उत्तर 24-परगना जिले के चांडपारा में तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक में ममता ने आरोप लगाया था कि मार्क्सवादियों ने उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए कांग्रेस और भाजपा से हाथ मिलाया है। यही नहीं, ममता ने भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा, राज्य में सेना की उपस्थिति को तख्ता पलट के रूप में देखा।[9] ज्ञात हो कि हाल ही में, आपातकालीन स्थिति में सैन्य अभियान के लिए रोड डाटा एकत्र वार्षिक अभ्यास के दौरान टोल प्लाजा में सेनाकर्मियों को तैनात किया गया था।[10]

8. "Mamata Banerjee Alleges Rivals' Plot To Eliminate Her", The Economic Times, June 20, 2013, http://economictimes.indiatimes.com/ news/politics-and-nation/ mamata-banerjee-alleges-rivals-plot-to-eliminate-her/articleshow/20672867. (Accessed Feb. 23, 2017).
9. Dibyangshu Sarkar, "I am vocal against demonetisation", Scroll. In, Dec 2 2016, /i-am-vocal-against-demonetisation-and-thus-this-military-coup-says-mamata-banerjee. (Accessed Feb. 24, 2017).
10. "Mamata To Protest 'Undemocratic Actions' Even As Army Rebuts Her Charges", HT,Dec 3 2016, http://www.hindustantimes.com/india-news/army-rebuts-mamata-charges-says-exercise-done-with-police-coordination/story-dxeVzqDfB0N6XuqAe5xnuM.html (Accessed Feb. 24, 2017).

ज्ञात हो कि हाल ही में, आपातकालीन स्थिति में सैन्य आंदोलन के लिए रोड़ डाटा एकत्र वार्षिक अभ्यास के दौरान टोल प्लाजा में सेनाकर्मियों को तैनात किया गया था।[11]

पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था

पश्चिम बंगाल की गौरवशाली विरासत शिक्षा, उद्योग तथा अन्य मोर्चों पर रही है। हालांकि वर्ष 1960 के दशक से राज्य की समग्र आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में गिरावट आई है। कम्युनिस्ट पार्टी के 34 वर्ष के शासन को अक्सर पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में ठहराव का कारण माना जाता है। जिसके बाद वर्ष 2011 में जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया था। तृणमूल कांगेस शासन के 6 वर्ष उपरांत पश्चिम बंगाल के आर्थिक आंकड़े किसी विकास का दर्पण नहीं दिखाते।[12] वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति की तस्वीर कोरी नजर आती है। गरीबी रेखा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल आज भी 5वें स्थान पर है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर 49 फीसदी (प्रति 1000) थी। शहरी क्षेत्रों में यह दर 56 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 47 प्रतिशत बताई गई है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया[13]

11. Aniruddha Ghoshal, "Mamata Banerjee Compares Situation In Bengal To 'Military Coup'", The Indian Express Dec. 2. 2016, http://indianexpress.com/article/india/mamata-banerjee-army-deployment-nh-2-in-west-bengal-military-coup-4405871/. (Accessed Feb.26. 2017).
12. Laveesh Bhandari, Minakshi Chakraborty, "Spatial poverty in West Bengal", Live Mint, March 23, 2015, http://www.livemint.com/Opinion/dXPv8bp492mKX-9rirXX0hK/Spatial-poverty-in-West-Bengal.html. (Accessed Feb. 13, 2017).
13. Ibid.

टाटा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी द्वारा किए गए रोजगार के वादे के बावजूद पिछले 5 वर्षों में कुछ भी रोजगार सृजित नहीं हुआ है।

ब्रिटिश उद्योग संगठन (सी.बी.आई.) और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूकेआईबीसी) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि ब्रिटिश उद्योग संगठन 'बंगाल जाने के बारे में चिंतित' है और उन्होंने माना कि राज्य 'व्यापार के अनुकूल नहीं है[14]

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस[15]

पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जिसमें जनसंख्या लगभग 1,029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या अनुपात के अनुसार कम जमीन होने के कारण, बंगाल का विकास और समृद्धि केवल कृषि से सम्भव नहीं है। ऐसे में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

14. Kountey Sinhal, " Bengal Falls Behind in FDI Race" , The Times of India, Sep 4 2015, http://timesofindia.indiatimes.com/india/Bengal-falls-behind-in-FDI-race/articleshow/48795936.cms (Accessed Feb. 13, 2017).
15. Ashok Gulati, Ranjana Roy, "From Plate to Plough: its not about loan waivers", The Indian Express, Feb. 27 , 2017, http://indianexpress.com/article/opinion/columns/election-commisssion-upa-government-agriculture-from-plate-to-plough-its-not-about-loan-waivers-4545171/. (Accessed Feb. 28, 2017).

(एफडीआई) एक जरूरी चीज बन जाती है, हालांकि इसे छोड़कर राज्य सरकार वर्तमान में दुर्भाग्य से बेरोजगारी, गरीबी और बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के मुद्दे से जूझ रही है।

पिछले 6 वर्षों में पश्चिम बंगाल के बकाया ऋण में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बंगाल सरकार के बजट दस्तावेजों के अनुसार राज्य का बकाया कर्ज वर्ष 2010-11 में करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए था जो 2015-16 में बढ़कर 3.05 लाख करोड़ रुपए हो गया। आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि दर 64 प्रतिशत है।[16]

पश्चिम बंगाल में मोटे तौर पर अशिक्षित मुस्लिम समुदाय की 55 प्रतिशत ग्रामीण और 60 प्रतिशत शहरी आबादी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। प्राप्त आंकड़े 'पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की लीविंग रिएलिटी' में सामने आये हैं। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि सरकार ने मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुसलमानों की आबादी राज्य की 27 प्रतिशत है।[17]

आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि राज्य में उच्च स्तर की गरीबी के बावजूद केवल 31.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार बीपीएल कार्ड धारक हैं और केवल 39.5 प्रतिशत मनरेगा कार्ड धारक हैं। भ्रष्टाचार और निरक्षरता ने मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से को सरकारी योजनाओं से दूर रखा। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इन योजनाओं में भारी मात्रा में मुसलमानों की अनुपस्थिति है। रोजगार के अवसरों और लाभ की पहुंच की कमी के परिणामस्वरूप मुस्लिम आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा दूसरे राज्यों में काम की तलाश में पलायन कर रहा है।

16. Namrata Acharya, "West Bengal's debt burden rises 64% six years", Business Standard, April 26, 2016, http://www.business-standard.com/article/economy-policy/west-bengal-s-debt-burden-rises-64-in-six-years-116042600053_1.html. (Accessed Feb. 26, 2017).
17. Esha Roy, " All Half of West Bengal Muslims do not have a job", The Indian Express, Feb. 29, 2016, http://indianexpress.com/article/cities/kolkata/over-half-of-west-bengal-muslims-do-not-have-a-job/. (Accessed Jan. 28, 2017).

घोटालों का राज्य

वर्तमान में पश्चिम बंगाल घोटालों को लेकर चर्चा का विषय रहा है जहां कुछ भ्रष्ट राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली ममता बनर्जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा राजनीति को दिया है। हालांकि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि उनकी इसी तपस्या की वजह से वह अपनी भ्रष्ट छवि पर पर्दा डालेंगी और उसे मुखौटे के रूप में प्रयोग करेंगी।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न घोटालों ने जब ममता बनर्जी का पर्दाफाश किया तब उनकी पार्टी के नेताओं और सदस्यों को गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी में शामिल पाया। कुछ मुख्य घोटालों की जानकारी को प्रस्तुत तालिका में दर्शाया गया है:[18]

Scams	Amount (in Crore)	Alleged Involvement of TMC Members
Saradha Scam (2008-2013)	30,000	Madan Mitra, Srinjoy Bose, Mithun Chakroborty, Kunal Ghose
Rose Valley (2013)	10,000	Sudip Bandyopadhyay, Tapas Pal
Narada Sting (2016)	NA	Mukul Roy, Sultan Ahmed, Sougata Roy, Suvendu Adhikari, Kakoli Ghosh Dastidar, Subrata Mukherjee, Firhad Hakim, Sovan Chatterjee
Silliguri Jalpaiguri Development Authority (SIDA, 2014)	NA	Gautam Deb, Subrata Mukherjee, Farhad Hakim and others

बंगाल में महिलाओं की स्थिति

एक समय 'सोने की भूमि' कहलाने वाली बंगाल की भूमि वर्तमान में सर्वोच्च अपराध की भूमि के रूप में जानी जाती है। जहां महिलाओं का सबसे अधिक शोषण होता है जबकि राज्य की बागडोर स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री के हाथों में है।[19] हाल ही में ममता से जब पूछा गया

18. Shreekumar Roy,, "Corporate scams and its impact on Indian Economy: A Case on 'Saradha Chit Fund'. Global Journal for Research Analysis, 3(11), 33-35,2014, (Accessed Feb. 24, 2017).
19. Suvojit Bagchi, "No law and order in West Bengal: Sonia", The Hindu, April 13, 2016, http://www.thehindu.com/elections/westbengal2016/sonia-gandhi-slams-mamata-banerjee-government/article8471649.ece. (Accessed Feb. 13, 2017)

कि "क्या राज्य की सभी महिलाओं का रेप किया जा रहा है" तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल राष्ट्र में तीसरे स्थान पर है जहां महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित हैं। द पार्क स्ट्रीट रेप केस, चरमपंथी कामधुनी सामूहिक बलात्कार, मानव तस्करी– ये सारे मामले ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार का रवैया निहायत उदासीन है। इन्हें राजनीतिक मुठभेड़ का विषय बनाकर वोट बटोरे जा रहे हैं। जैसे "शाहजानो घोटोना"[20] 'कामधुनी बलात्कार' मामला न्याय और सत्ता शासित राजनीति का एक ज्वलंत उदाहरण है। कामधुनी बलात्कार मामले में कॉलेज से परीक्षा देकर आ रही एक 20 वर्षीय छात्रा का अपहरण किया गया और सामूहिक बलात्कार कर बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। जिसके बाद बंगाल के सुस्त शासन ने देरी से कार्रवाई की और मामले के 8 में से 6 अपराधियों को इसलिए छूट दी गई क्योंकि वे अल्पसंख्यक थे। जाहिर है कि सरकार के लिए बलात्कारी इंसान नहीं बल्कि किसी जाति या समुदाय का हिस्सा बन गया।[21] साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस घटना से अपना राजनीतिक लाभ भी सुनिश्चित किया। खबरों के मुताबिक मुख्य आरोपी तृणमूल प्रधान के रिश्तेदार थे और वे अल्पसंख्यक वोट बैंक समुदाय के थे।[22] बंगाल में ज्यादातर अपराध अल्पसंख्यकों द्वारा किए जाते हैं क्योंकि वे ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक का

कामधूनी रेप और मर्डर केस पर निर्णय के दौरान न्यायालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता[23]

20. Soudhriti Bhabani, "Mamta Banaerjee's Minority Appeasement Draws Flak from Right, Left and Centre", India Today, Jan. 28, 2016, http://indiatoday.intoday.in/story/mamata-banerjees-minority-appeasement-draws-flak-from-right-left-and-centre/1/581364.html (Accessed Feb. 15, 2017)
21. Ibid.
22. "No Women is safe in West Bengal today", Rediff.com, July 27, 2013, http://www.rediff.com/news/column/no-woman-is-safe-in-west-bengal-today/20130727.htm. (Accessed Feb. 17, 2017).
23. http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3424646/Justice-Bengal-s-Nirbhaya-Three-brutal-Kamduni-gang-rape-convicts-death-sentence-life-term.html

कार्य करते हैं। इसका फायदा वह हत्या और बलात्कार करके ले लेते हैं।[24] वर्तमान समय में अपराध से बचने के लिए राजनीतिक पार्टी के नेताओं से संबंध बनाकर उसका फायदा उठाया जा रहा है।

रमना गांव, जो रघुनाथगंज पुलिस थाने के अंदर आता है, वहां एक 11 वर्षीय हिन्दू लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ मुस्लिमों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया है। जिसके बाद गांव ने भी मिलकर मुर्शीदाबाद जिले में हुई इस घटना की निंदा की और आवाज उठाई। पुलिस इस सबके बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा बेकाबू हो गया और वे अपराधी के घर पहुंचे, जहां मौके पर पुलिस ने आकर ग्रामीणों को रोक लिया। यह केवल एक घटना नहीं जब पुलिस ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की। ये घटनाएं बंगाल में आम हैं। इसी के चलते ओस्मान और उसके गुंड़ों ने 15 वर्षीय अनुसूचित जाति समुदाय की लड़की का बलात्कार कर 20,000 नगद और अन्य महंगी वस्तुएं लूट लीं। यह घटना झूपखली गांव में हुई थी।[25]

2010-2015 के बीच पश्चिम बंगाल में बच्चों के प्रति अपराध बढ़ गए थे।[28]

इन सभी घटनाओं को देखते हुए केवल यही कहा जा सकता है कि बंगाल में महिलाओं की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तृणमूल सरकार ने राजनीतिक शक्ति का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं के फुटबाल खेलने की अनुमति को केवल मौलवी की मांग से रद्द कर दिया। महिला फुटबाल खिलाड़ियों की मांग को नजरअंदाज किया। इसके चलते टीएमसी को निर्धारित फुटबाल मैच रद्द करना पड़ा। इन सभी घटनाओं को देखते हुए केवल यही कहा जा सकता है कि बंगाल में महिलाओं की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तृणमूल सरकार ने शक्ति का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं के फुटबाल खेलने की अनुमति को केवल मौलवी की मांग से रद्द कर दिया। महिला फुटबाल खिलाड़ियों की मांग को नजरअंदाज किया। इसके चलते टीएमसी को निर्धारित फुटबाल मैच रद्द करना पड़ा।[26] इस मामले को लेकर यह बताया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री सानित्रि मित्रा ने इस प्रतिबंध का समर्थन किया और साम्प्रदायिक तनाव की आशंका के चलते जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श के बाद मैच रद्द कर दिया गया।[27]

24. "Newlywed gang-raped", The Times of India, May 22, 2014,http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Newlywed-gang-raped/articleshow/35450986.cms?cfmid=2000000. (Accessed Feb. 18, 2017).
25. "*Ground Report: The State of Hindus in West Bengal*", Indiafcts, June 6, 2014, http://indiafacts.org/ground-report-state-hindus-west-bengal/. (Accessed Feb. 22, 2017).
26. "Mamta Banerjee's men stop women's football match on demand from muslim clerics", DNA, March 17, 2015, http://www.dnaindia.com/sport/report-mamata-banerjee-s-men-stop-women-s-football-match-on-demand-from-muslim-clerics-2069503. (Accessed Feb. 14, 2017)
27. "WB: Hardliners ban women's football match as jerseys are 'too tight'", Hindustan Times ,March 16, 2015, http://www.hindustantimes.com/india/wb-hardliners-ban-women-s-football-match-as-jerseys-are-too-tight/story-S8NZACR8vyWt2CUhq3krlM.html. (Accessed Feb. 17, 2017)
28. Himadri Ghosh, "West Bengal, Epicentre Of India's Boom In Sexual Slavery" ,Indiaspend, April 23, 2016, http://www.indiaspend.com/cover-story/west-bengal-epicentre-of-indias-boom-in-sexual-slavery-43863. (Accessed Feb. 22, 2017).

पश्चिम बंगाल में 2014 के दौरान नाबालिग लड़कियों की तस्करी सबसे अधिक थी

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का वर्ष-वार सांख्यिकीय रिकॉर्ड[29]

अलोकतांत्रिक और अनैतिक कार्रवाई

बंगाल अपने लोकतांत्रिक मूल्य व वास्तविकता को नजरअंदाज कर हिंसा की घटनाओं व अपराधियों को बढ़ावा देकर उनका समर्थन कर रहा है। अनैतिक लोगों को सत्ता का आशीर्वाद मिल रहा है जिससे अनैतिक कार्य और बढ़ रहे हैं। ऐसे कुछ उदाहरण निम्न हैं-

- जानकीनगर गांव के वापी पाल, जिन्होंने नागरिक पुलिस के रूप में काम किया। जिसे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने फेसबुक पर ममता बनर्जी के खिलाफ "अपमानजनक टिप्पणी" करने के लिए हरिश्चंद्रपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया।[30]
- अप्रैल, 2012 को जादवपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने बनर्जी और तत्कालीन रेलमंत्री मुकुल रॉय के साथ पूर्ववर्ती दिनेश त्रिवेदी का कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।[31]
- पूर्व केन्द्रीय रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी को ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि त्रिवेदी ने नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ रेल सुरक्षा के लिए यात्रियों के किराए में वृद्धि की थी। बनर्जी ने इसे लेकर तर्क दिया था कि त्रिवेदी ने किराए बढ़ाने से पहले उनसे अनुमति नहीं ली। जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

29. National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Crime in India ,Compendium (2011-2015), (Accessed Feb. 22, 2017).
30. "Youth Arrested For Making Anti-Mamata Banerjee Remark On Facebook", TOI, Oct. 15, 2014, http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Youth-arrested-for-making-anti-Mamata-remark-on-Facebook/articleshow/44828692.cms) . (Accessed Feb. 21, 2017).
31. Ibid.

- तृणमूल कांग्रेस द्वारा अशोक भट्टाचार्य, सुदर्शन रे चौधरी, अब्दुर रज्जाक मोल्ला, विपिन चौधरी और अन्य वाम मोर्चे, कांग्रेस और भाजपा के लोगों पर हिंसक हमले की एक श्रृंखला रही है।[32]

- हाल ही में भाजपा के राज्य मुख्यालय के पास बड़ी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया था क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के क्रोधित कार्यकर्ताओं ने तीन हफ्ते तक पार्टी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को घेर रखा था ताकि उनकी गिरफ्तारी रोकी जा सके।[33] साथ ही ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके सांसद की टिप्पणी का समर्थन किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए 'चूहे' शब्द का इस्तेमाल किया था।[34] ममता ने कहा था "उन्होंने सोचा कि टीएमसी नरम मिट्टी पर है, तो हमें उन्हें ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन याद रखना तृणमूल कांग्रेस उपजाऊ मिट्टी पर खड़ी है। हम चूहों से परेशान नहीं हैं हम बाघों से लड़ते हैं।[35]

- साथ ही ममता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना अपमानजनक तरीके से आलोचना की। ममता ने कहा "गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे जो साथ हैं तो अच्छा है, जो नहीं हैं तो दुश्मन लगते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये जनता की बात है।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस[36]

32. "Trinamool MP Arrest: BJP office attacked, CRPF–RAF deployed", Web India 123, Jan 3, 2017, http://news.webindia123.com/news/Articles/India/20170103/3026072.html. (Accessed Feb. 21, 2017).
33. Ibid.
34. Sougata Mukhopadhyay, "With Rude Remarks Against PM, TMC MP Kalyan Banerjee Hits New Low", Battle of the States, Jan. 11, 2017, http://www.news18.com/news/ india/trinamool-congress-mp-kalyan-banerjee-hits-a-new-political-low-note-1334436.html. (Accessed Feb. 24, 2017).
35. Ibid.
36. ibid.

- ममता का गैर-जिम्मेदार व्यवहार और दमनकारी प्रकृति से अंततः जनता तंग आ गई क्योंकि उनके द्वारा बोलने की आजादी का गलत लाभ उठाया जाने लगा और कई बैठकों पर रोक लगाई जाने लगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक रैली को इजाजत नहीं दी गई जिसे डॉ. मोहनराव भागवत सम्बोधित कर रहे थे[37] जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुमति ली गई और रैली आयोजित की गई। जाहिर है कि ममता उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने केवल अपने मन की करते हुए सत्ता पर केवल अपना शासन चलाने का प्रयास किया है।
- पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासन और कोलकाता पुलिस के कथित दबाव के कारण प्रतिष्ठित कलकत्ता क्लब द्वारा एक संगोष्ठी 'बलूचिस्तान और कश्मीर की गाथा' को अनुमति से वंचित कर दिया गया। 7 जनवरी, 2017 को कलकत्ता क्लब में होने वाले इस आयोजन को अंतिम समय में क्लब के अधिकारियों ने अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया।[38] हालांकि उस घटना के बाद बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए लेखक तारेक फतह ने ट्विटर पर लिखा, "इस्लामवादियों का डर, ममता सरकार तारेक फतह को बोलने से रोक रही है"।[39]
- केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल में एक संसद मेला आयोजित करना चाहते थे। आम लोगों के लिए जो सुविधाएं सरकार देती है जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य प्रशासनिक दस्तावेजों को जारी करने के लिए 'संसद मेला' का आयोजन आसनसोल नगर निगम के महापौर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे मंजूरी दे दी।[40]

तुष्टीकरण की नीति

इन छह वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार द्वारा अपनाई गई मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बड़े स्तर पर पश्चिम बंगाल में हिंसा और विनाश का कारण बनी है। ममता बनर्जी के समर्थन की आड़ लेते हुए अल्पसंख्यक मुस्लिमों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ मिलकर इन छह सालों में दंगों को भड़काते हुए पश्चिम बंगाल को गर्त में पहुंचा दिया है।[41] बनर्जी सरकार की वोट बैंक की राजनीति ने बंगाल को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केंद्र बना दिया। पश्चिम बंगाल पूरे राष्ट्र को यह स्मरण कराता रहेगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का केवल एक ही परिणाम निकलेगा-इस्लामिक कट्टरता का उदय तथा अलगावाद और पूर्ण रूप से कानून और व्यवस्था का ध्वस्त होना।

37. Arkamoy Majumdar, "RSS Not Opposed To Other Faiths, Says Mohan Bhagwat At Kolkata Rally", Livemint, Jan. 15, 2017, http://www.livemint.com/Politics/kqkoEZcJX2qZ8Ocl5U7KDL/RSS-not-%20opposed-to-%20other-faiths-%20says-Mohan-%20Bhagwat-at-%20Kolka.html. (Accessed Feb. 2, 2017).
38. Indrajit Kindu, "Kashmir Event Banned At Prestigious Calcutta Club Due To Kolkata Police Pressure", India Today, Jan. 5, 2017, http://indiatoday.intoday.in/story/ exclusive-kashmir-event-banned-calcutta-club-kolkata-police/1/850009.html. (Accessed Feb. 9, 2017).
39. Ibid.
40. Manogiya Loiwal, "Asansol Mayor Denies Babul Supriyo Permission To Hold Sansad Mela Fearing Stampede", India Today, Jan. 11, 2017, http://indiatoday.intoday.in/story/asansol-mayor-babul-supriyo-sansad-mela-calcutta-high-court-stampede-fear/1/855283.html. (Accessed Feb. 9, 2017).
41. Suvrajyoti Gupta, "Can Hindutva Re-establish itself in West Bengal politics?", Swarajya, Dec. 30, 2016, https://swarajyamag.com/politics/ can-hindutva-re-establish-itself-in-west-bengal-politics.(Accessed Feb. 10, 2017).

ममता बनर्जी सत्ता में बने रहने की लालसा के कारण मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दे रही हैं। इसका बंगाल पर काफी बुरा प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का संरक्षण, समुदायों में कट्टरता को बढ़ावा देता है और अतीत में प्रत्यक्ष रूप में हिंदुओं पर जो हमले हुए वे इसके उदाहरण हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 2.4 करोड़ थी। समझने वाली बात यह है कि इसी साल में जहां पूरे देश में मुस्लिम आबादी 0.8 फीसदी बढ़ी थी, वहीं सिर्फ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी में 1.77 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।[42]

बंगाल के कई जिलों में हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी से कम है। जैसे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी 33.21 फीसदी[43], मालदा में 47.99 फीसदी और उत्तरी दीनजपुर में 49.31 फीसदी है। पश्चिम बंगाल में केवल एक ही कार्य लगातार हो रहा है और वह है वहां की आबादी का विषमता से प्रसार होना। ममता बनर्जी ने साम्प्रदायिक राजनीति को राज्य का मुद्दा बनाया। साम्प्रदायिक राजनीति के साथ फासीवादी विचारधारा को साथ लेते हुए उन्होंने सम्प्रदाय विशेष के लिए कार्य किया है और प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। बनर्जी सरकार का इतने सालों का खाका तैयार करते समय यह समझ आ गया है कि वह यथार्थ से परे तुष्टीकरण की नीति के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिमों का समर्थन कर रही है। उनके तुष्टीकरण की नीति के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं–

- मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की उपन्यासकार तस्लीमा नसरीन का पश्चिम बंगाल में आना प्रतिबंधित कर दिया। इतना ही नहीं मुस्लिम कट्टरपंथियो की संतुष्टि के लिए उन्होंने तस्लीमा के टीवी सीरियल पर भी प्रतिबंध लगा दिया।[44] राष्ट्रविरोधी गतिविधियां और भाषण देने वाले टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना नुरुर रहमान बरकती ने तस्लीमा को मारने का फतवा जारी किया।

नमाज़ अदा करती हुई ममता बनर्जी

स्रोत: जनगणना 2011

42. http://censusindia.gov.in/2011-common/CensusDataSummary.html (Accessed Feb. 7,2017).
43. Govt of India, "WBSMB : Population Details" 2017 , Wbagrimarketingboard.Gov.In. http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.htm. (Accessed Feb. 7, 2017).
44. "Mamta Banerjee turned out harsher than Left in my case", The Indian Express, Jan. 22, 2017, http://indianexpress.com/article/india/mamata-banerjee-turned-out-harsher-than-left-in-my-case-taslima-nasreen-4486028/ (Accessed Feb 18, 2017).

नुरुर रहमान बरकती के साथ ममता बनर्जी

- यही, मौलवी सैयद मोहम्मद नुरुर रहमान बरकती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नोटबंदी को लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कलकत्ता प्रेस क्लब में तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें बरकती ने भाषण दिया। आतंकी ओसामा बिन लादेन का अनुसरण करने वाले बरकती ने प्रधानमंत्री मोदी को जातिवादी बताया और ममता बनर्जी को साम्प्रदायिक सौहार्द्र का द्योतक बताया।[45]

- लगातार पिछले चार सालों से बीरभूम जिले के एक गांव में सरकार 25 मुस्लिम परिवारों को खुश करने के लिए 300 हिंदू परिवारों को पारंपरिक दुर्गा पूजा का आयोजन करने की इजाज़त नहीं दे रही है।[46] अब आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में उन्हें पूजा का

45. "Muslim Cleric Close To TMC Issues Fatwa Against Narendra Modi", The Hindu Business Line, Jan. 7, 2017, http://www.thehindubusinessline.com/news/ national/muslim-cleric-close-to-tmc-issue-fatwa/article9466268.ece. (Accessed Feb. 9, 2017).
46. Jaideep Majumdar, "West Bengal is turning into communal tinder box, thanks to Mamta Banerjee", Swarajya, Dec. 22, 2016, https://swarajyamag.com/politics/ west-bengal-is-turning-into-a-communal-tinderbox-thanks-to-mamata-banerjee.(Accessed Feb. 21, 2017)..

मूल अधिकार ही नहीं मिल रहा है तो वे बाकी और किन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। बंगाल जिसे मां दुर्गा की पूजा का गढ़ माना जाता था आज वहां केवल मुस्लिम बिना किसी डर के अपने त्योहार मना रहे हैं।

- तुष्टीकरण की नीति के परिणामस्वरूप मुसलमानों ने बंगाल को इस्लाम का गढ़ बना दिया है और जब भी हिंदुओं के धार्मिक आयोजन होते हैं तो मुसलमान बिना डरे अशांति पैदा करते हैं। अभी हाल की घटना बीरभूम जिले में घटी, वहां मुसलमानों ने हनुमान मंदिर को ध्वस्त कर दिया और मूर्ति को मंदिर से बाहर फेंक दिया। मयूरेश्वर थाना ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, कानून किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया। यह घटना दिखाती है कि ममता सरकार किस हद तक तुष्टीकरण कर रही है।[47] हिन्दुओं के अपमान की यह घटना डरावने संकेत भी देती है। यह समाचार पश्चिम बंगाल के कथित सेक्युलर मीडिया के किसी चैनल पर नहीं दिखाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसे पूरी तरह कपोल-कल्पित बताया गया। यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का कितना नियंत्रण एवं प्रभुत्व है। जहां पर हिन्दुओं को यह भी अधिकार नहीं है कि वे अपने लिए मंदिर निर्माण या पूजा-पाठ करे। सत्ताधारी पार्टी,

कोलकाता प्रेस क्लब में बैठक के दौरान टीएमसी सांसद इदरिश अली के साथ बरकती

47. Anand, "Hanuman Temple destroyed", Satyavijayi, May 16, 2016, https://satyavijayi.com/hanuman-temple-destroyed-idol-thrown-road-bengal-no-fir-registered/ (Accessed Feb. 24, 2017).

स्थानीय प्रशासन और पुलिस सब मिलकर कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रहे हैं। सरकार अविश्वनीय रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है।[48]

पश्चिम बंगाल में हिन्दू जीवित रहें या मरें; हर तरह से, उनके भौतिक अस्तित्व को निशाना बनाया जाता है। अर्जनपुर में हिन्दू परिवारों को विरोध का सामना करना पड़ा। जब वीरेनपाल का दाह संस्कार किया जा रहा था तो उसे रोका गया। तब पता चला 300 वर्षों से श्मशान का उपयोग करने वाले हिन्दू वहां से बेदखल कर दिए गए हैं। उन लोगों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जैसा एक स्थानीय निवासी ने दावा किया कि '300 वर्षों के बाद हम लोगों को कहा गया कि दाह संस्कार यहां पर नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन ने उस जगह से 15 किमी. दूर श्मशान के लिए जगह देने का वादा किया। वहां की पुलिस भी उस जमीन को (जिस जमीन पर हिन्दुओं का अधिकार था) वापस देने से डर गयी।[49]

- पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण किया जा रहा है। यह काम द्रुतगामी गति से ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की तीव्रता बंगाली कला-संस्कृति पर आघात है। यह काम राज्य की शिक्षा प्रणाली के द्वारा किया जा रहा है। सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में 'रंगधोनू' (इन्द्रधनुष) के पर्याय के रूप में प्रचलित 'आकाशी नीला' शब्द को 'आसमानी' (जोकि उर्दू का शब्द है) के स्थान पर बदल दिया गया है।[51]

बीरभूम में मंदिर ध्वस्त करने के बाद सड़क पर फेंकी गई हनुमान मूर्ति[50]

48. Upendra Bharti, "Bajrangbali Temple Destroyed By Muslims near Mayureswar", Struggle for Hindu Existence, May 14, 2016, https://hinduexistence.org/2016/05/14/bajrangbali-temple-destroyed-by-muslims-near-mayureswar-hindus-protesting-in-birbhum-wb/. (Accessed Feb. 29,2017).
49. https://www.youtube.com/watch?v=SBkHZOQjN1o. (Accessed Feb. 23, 2017).
50. https://hinduexistence.org/2016/05/14/bajrangbali-temple-destroyed-by-muslims-near-mayureswar-hindus-protesting-in-birbhum-wb/html
51. "Islamisation of Education shows where West Bengal is headed", Hindupost, Jan. 13, 2017, http://www.hindupost.in/news/islamization-education-shows-west-bengal-headed/ (Accessed Feb. 24, 2017).

पश्चिम बंगाल पर संगोष्ठी: भारत नीति प्रतिष्ठान की पहल

भारत नीति प्रतिष्ठान (आई.पी.एफ) की ओर से पश्चिम बंगाल पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में चर्चा का विषय था– 'लोकतंत्र, हिंसा और राज्य'। इस संगोष्ठी का आयोजन 21 जनवरी, 2017 को कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में हुआ। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजीजू, नई दिल्ली से लोकसभा सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, कर्नल दीप्तांशु चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक मलिक थे। इस संगोष्ठी में बहुत से साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित लोग भी वहां उपस्थित थे जिन्होंने इन दंगों में होने वाले खौफनाक अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथियों ने पुस्तिका 'मिनी डायरेक्ट एक्शन इन पश्चिम बंगाल' (Mini Direct Action in West Bengal) का विमोचन भी किया। यह पुस्तिका भारत नीति प्रतिष्ठान की तरफ से तैयार की गई थी। इस पुस्तिका के शोध कार्य का मुख्य केन्द्र पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा असंवैधानिक, अलोकतंत्रवादी और उनकी जबर्दस्ती की नीतियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई हिन्दू विरोधी प्रवृत्ति पर भी ध्यान आकर्षित करना था।

आईपीएफ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित पश्चिम बंगाल दंगों के पीड़ित

इस अवसर पर प्रतिष्ठान के मानद निदेशक प्रो. राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस तरह वैचारिक राजनीति को पछाड़कर व्यक्तित्व और पहचान की राजनीति आगे बढ़ रही है, कुछ उसी तरह का कार्य पश्चिम बंगाल में हो रहा है। सन् 1970-1980 के बाद से वैचारिक राजनीति का क्षय हो रहा है। पंथ और पहचान की राजनीति महत्वपूर्ण हो चुकी। प्रो. राकेश सिन्हा ने आगे कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से चुनाव तो जीत गईं लेकिन उनके पास अपने राज्य और वहां के लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई विकास का खाका नहीं है। ममता बनर्जी वहां पर हिटलर और मुसोलिनी की नीतियां अपना रही हैं। प्रो. सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना के भड़काने पर कोलकाता में जो हत्याएं हुई थी, उस दौरान न तो जवाहरलाल नेहरु और न ही महात्मा गांधी ने पीड़ितों से मिलने की कोशिश की। आज पश्चिम बंगाल कुछ इसी तरह के माहौल का सामना कर रहा है, जहां हिन्दुओं को डराया, धमकाया जा रहा है।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजीजू ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक है। उन्होंने कहा जहां-जहां भी लेफ्ट फ्रंट सरकार थी; चाहे वह केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या त्रिपुरा हो सभी जगह से लोकतंत्र समाप्त हो चुका था। उन्होंने यह भी

कहा कि समस्या यह थी कि देश पर केवल बाहर से ही प्रभाव नहीं पड़ रहा था बल्कि भीतर से भी प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि राज्य में शासित सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा देती है। उन्होंने कुछ लोगों का जिक्र भी किया जो मानते हैं कि भारत भविष्य में इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कमजोरी हमारे भीतर ही है और उस पर हमें काबू पाना है। श्री रिजीजू के अनुसार देश कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ममता सरकार बाकी सभी चीजों को ताक पर रखकर केवल एक ही समुदाय को संतुष्ट करे। उनकी यह योजना नाकाम होगी। उन्होंने दावा किया कि देश के बारे में झूठी खबरें प्रचारित की जा रही है। अगर भारत देश और यहां के हिन्दू असहिष्णु हैं तो पूरे विश्व से शरण ार्थी शरण पाने के लिए भारत ही क्यों आते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि भारत के अलावा उन्हें कहीं और शरण नहीं मिलेगी!

संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए श्री किरेन रिजीजू

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बंगाल केवल बंगालियों के लिए नहीं है बल्कि यह पूरे देश का है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य ऐसे दर्शाता है जैसे बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जनसांख्यिकी बदलाव, असहिष्णुता, इस्लामीकरण, जिहादवाद, घुसपैठ और नरसंहार पर भी बातचीत की। जनसांख्यिकी परिवर्तन ने एक समुदाय की जनसंख्या में बदलाव ला दिया और इस बदलाव के पीछे का मुख्य कारण जिहादवाद था। श्रीमती लेखी ने कहा "समस्या इस्लामीकरण नहीं है, जिहादवाद है"।

दंगा पीड़िता के साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी

कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने कहा कि राज्य में चीजें हाथ से बाहर जा चुकी हैं। अनाधिकारिक रूप से राज्य में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 34 प्रतिशत थी, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27 प्रतिशत थी। पश्चिम बंगाल की अल्पसंख्यक जनसंख्या में लगभग 14 फीसदी का इजाफा हुआ है। अनाधिकारिक रूप से से देखा जाए तो भारत में 4 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम घुसपैठिए रह रहे हैं लेकिन अधिकारिक रूप से इनकी गणना मात्र 2 करोड़ है। दरअसल, वे अभी भी उसी रणनीति का अनुसरण कर रहे है जिसका पालन वह 1947 से कर रहे थे।

संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए श्री अशोक मलिक

वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक मलिक ने कहा कि ढेर सारे जिहादी बॉर्डर पार बांग्लादेश सरकार के कारण आए क्योंकि वहां की सरकार जिहादियों को लेकर काफी सख्त है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिहादियों को सिर चढ़ाया जा रहा है। भारत में गुलाम अली के कार्यक्रम का आयोजन जब शिवसेना ने नहीं होने दिया तब ममता बनर्जी सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के खर्चे पर उनके कार्यक्रम का आयोजन करवाया। उनकी यह हरकत खतरे की घंटी की तरह है।

पश्चिम बंगाल पर हुई इस संगोष्ठी में बंगाल के 6 पीड़ित भी शामिल हुए। उनमें से एक पीड़ित ने बंगाल में उनके साथ हुए भयानक दमन की गंभीर तस्वीर सबके सामने रखी। उस पीड़ित ने बताया कि 'उन्हें दिल्ली आने की इजाजत नहीं थी क्योंकि अगर उन्होंने अपने साथ घटित हुई पीड़ादायक कहानी बताई तो पूरे विश्व को राज्य में हो रही दुर्घटनाओं की जानकारी हो जाएगी। उस पीड़ित ने यह भी बताया कि मीडिया भी बनर्जी सरकार के प्रभाव में है क्योंकि वहां मीडिया रिकार्ड तो सब करती है लेकिन न्यूज चैनल्स में कुछ भी नहीं दिखाया जाता। हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दंगा पीड़ितों को 35,000 रुपए की राशि चेक से दी जानी थी लेकिन वह राशि यानी चेक मुसलमानों में ही वितरित कर दिए गए। पीड़ित ने आगे यह भी बताया कि दंगों के बाद हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम लोग ले गये और उनका शारीरिक शोषण किया। कुछ घंटों बाद उन्हें वापस छोड़ दिया। उसने यह भी बताया कि वहां की भीड़ पाकिस्तान का झंडा लहराती है और उनके पक्ष में नारे लगाती है।'

अन्त में सभी वक्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि पश्चिम बंगाल की समस्या केवल बंगालियों की नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष की है। इस बात पर भी सब सहमत हुए कि हमारे देश की कुछ आंतरिक कमियों के कारण भारत में इस प्रकार की समस्या उभर कर सामने आ रही हैं।

शमशान को कब्रिस्तान बनाने पर मीडिया की रिपोट (स्रोत: न्यूज़ एक्स)

- स्कूलों में सरस्वती पूजा कार्यक्रम को बाधित करने के उद्देश्य से मुसलमानों ने नबी दिवस समारोह मनाने की अनुमति मांगी। बिना किसी अनुमति के इस्लामिक कट्टरपंथी समूह और छात्रों (जो हावड़ा जिले से थे) ने जोर जबर्दस्ती स्कूलों में घुसकर प्रोफेट मोहम्मद के जन्मदिन को मनाने के लिए स्कूल कैम्पस में अराजकता फैलाई। स्कूल के अंदर मुस्लिमों ने जबर्दस्ती एक मंच बनाकर वातावरण को तनावग्रस्त बनाया और स्कूल को स्कूल इंस्पेक्टर के द्वारा बंद करा दिया गया। उसने कारण बताया कि इस स्कूल में प्रशासनिक समस्या है। स्कूल कई महीनों तक बंद रहा और सरस्वती पूजा त्योहार मनाने की इजाजत नहीं मिली।[52]

द तहट्टा हाईस्कूल 29 नवम्बर को बंद था
(स्रोत: शुभम दत्ता/इंडियन एक्सप्रेस)

52. "School closed Bengal", Swarajya, Feb. 1, 2017, https://swarajyamag.com/insta/school-closed-in-bengal-after-islamists-forcefully-celebrate-nabi-diwas-on-premises-vandalise-property (Accessed Feb. 17, 2017).

- साम्प्रदायिक कटुता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में 11 जनवरी, 2017 को पुस्तकालयों में नबी दिवस मनाने का आदेश पारित किया। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में भी नबी दिवस मनाने को अनिवार्य बनाने के लिए आदेश जारी किया।[53]

- ममता बनर्जी ने मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उर्दू भाषा का प्रवेश कराया। सच्चर कमेटी के सहयोग से उन्होंने कई मुस्लिम विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए। मदरसों में तकनीकी शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान रखा।[54] ममता ने राज्य के 12 जिलों में दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू रखी। हैरानी की बात यह है कि इन जगहों पर मुस्लिम आबादी कुल आबादी की मात्र 10 फीसदी है। उनके शासन के दौरान कोलकता में स्थित आलिया मदरसे को अरबी और फारसी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। पूरे देश में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां 2 लाख से ज्यादा इमामों और मुआजिमों को सरकारी खजाने से 7000 से लेकर 10000 रुपए तक की तनख्वाह दी जाती है।

- ममता बनर्जी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पारित किया। इस बजट में उन्होंने एक बड़ी धनराशि अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों की शिक्षा के लिए आवंटित की। यह राशि 2815 करोड़ के लगभग थी जो कि बड़े उद्योग, छोटे और मध्यम उद्यमियों, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कुल खर्चे से भी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम वोट बैंक को आवासीय और तुष्टीकरण की नीति से रिझाते हुए वे पश्चिम बंगाल को 'सलाफी जिहाद' की ओर धकेल रही हैं। मदरसों के लिए धनराशि आवंटित करते हुए वे उन मुल्लाओं को बढ़ावा दे रही हैं जो कि बंगाल में ही छोटे-छोटे इस्लामिक राज्य बना रहे हैं या बना चुके हैं। इतना ही नहीं उनकी इस नीति ने हिंदू आबादी को द्वितीय श्रेणी

Government of West Bengal
Directorate of Library Services,
Bikash Bhawan, 9th Floor, North Block, Salt Lake City,
Kolkata- 700 091
Phone No.: (033) 2358-5742, 2359-4279, Fax: (033) 2359-4279
E-mail ID: dlsws1986@gmail.com

Memo No. : 78/LS
OM/Lib-11/1993(Pt.1)
Dated: 11.01.2017

From : Director of Library Services,
West Bengal

To The District Library Officer/ Additional District Library Officer,

Sub : Celebration of Important Events in different libraries in West Bengal for the Calendar year 2017.

As desired by the Hon'ble MOS(IC), ME&LS Dept., you are hereby requested to take necessary arrangements to observe all the dates and events as enclosed list including birth day of Syed Mir Nisar Ali Titumir (on 27th January) in each library and to give feedback to this Directorate every month.

Each Library would be given Rs. 1,000/- for each event. They are free to mobilize local resources to augment above fund if considered necessary.

This may be treated as very important.

Encls: As stated

Director of Library Services,
West Bengal

Memo No. : 78/LS
OM/Lib-11/1993(Pt.1)
Dated: 11.01.2017

Copy forwarded for information to

1. Sabhadipati,
2. The District Magistrate and Chairman, Local Library Authority,
3. P. S. to HMOS(IC), Dept. Of ME & LS,
4. PA to the Secretary, Dept. Of ME & LS,
5. The Guard File

Director of Library Services,
West Bengal

राज्य के सरकार पुस्तकालयों में सैयद मीर निसार अली तितुमीर का जन्मदिन मनाने के लिए सरकारी आदेश

53. Indrajit Kundu, "New controversy in West Bengal...", India Today, Feb. 15, 2017, http://indiatoday.intoday.in/story/controversy-west-bengal-govt-order-nabi-diwas-libraries/1/883762.html. (Accessed Feb. 19, 2017).
54. Bijoy Menon, "Mamta's Token of .....gain", Panorama, Jan. 2016, http://www.easternpanorama.in/index.php/music/155-2016/january-2016/3179-january-2016-politics-4 (Accessed Feb. 27, 2017)

का नागरिक बना दिया है। वास्तव में देखा जाए तो हिंदुओं की स्थिति उन साधारण नागरिकों की तरह है जिनका खुद का घर नर्क से भी बदतर होता जा रहा है।[55]

- ममता बनर्जी हर एक तरीका अपना रही हैं जिससे मुसलमानों को संतुष्ट किया जा सके। उन्होंने राज्य में रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जिसमें 10 प्रतिशत मुसलमानों और 5 प्रतिशत दूसरे अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था, उसे भी ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तरह से मान लिया।

- ममता बनर्जी का अल्पसंख्यकपरस्त संकीर्ण दृष्टिकोण, विकास के हर एक श्रेणीबद्ध कदम से दूर दिखाई पड़ता है। 2012 में बनर्जी ने बहुत ही शर्मनाक ढंग से स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों को सबसे ज्यादा छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। छात्रवृत्ति के साथ-साथ 2500 रुपए प्रत्येक मस्जिद के इमाम और 1000 रुपए उसके रख-रखाव करने वालों को भी दिए गए। इस तरह का अनुदान राज्य के वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया गया। जिससे 32000 मस्जिदों के इमामों को फायदा हुआ।[57] यह अनुदान बंटवारा कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद सामने आया। इसे उजागर करने में भाजपा की बड़ी भूमिका रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे असंवैध

पश्चिम बंगाल में विभिन्न विभागों के लिए आवंटित योजनाएं
(स्रोत: *thelotpot.com*)

55. "Health Ministry takes a progressive…health", Swarajya, Feb. 21, 2017, https://swarajyamag.com/insta/health-ministry-takes-a-progressive-view-in-its-resource-material-on-adolescent-health. (Accessed Feb. 22, 2017).
56. "Shocking Muslim Appeasement", Thelotpot, Feb. 13, 2017, http://www.thelotpot.com/shocking-muslim-appeasement-by-mamata-banerjee-see-what-she-did-in-the-budget/html (Accessed Feb. 25, 2017).
57. Jaideep Mazumdar, " West Bengal is turning into communal tinder box, thanks to Mamta Banerjee" , Swarajya, Dec. 22 ,2016, https://swarajyamag.com/politics/west-bengal-is-turning-into-a-communal-tinderbox-thanks-to-mamata-banerjee.(Accessed Feb. 21, 2017).

ानिक करार दिया।[58] कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 'यह एक स्पष्ट नियोजित तथ्य है कि राज्य किसी विशेष धर्म का संरक्षण या समर्थन नहीं कर सकता है'। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की आधारभूत संरचना का एक भाग है। अत: राज्य अपने आपको किसी विशेष धर्म का अनुरक्षण या समर्थन करके अपनी पहचान नहीं बना सकता। राज्य का दायित्व है कि सभी धर्मावलम्बियों के साथ एक जैसा व्यवहार करे।[59]

- ममता बनर्जी की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीति उसकी शिक्षा नीति से स्पष्ट हो जाती है। पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री घटक ने आसनसोल में घोषणा की कि मुस्लिम स्कूलों को सहायता दी जाएगी। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 4.25 लाख की राशि और हाईस्कूल को 11 लाख की राशि मिलेगी। समझा जा सकता है कि सरकार की यह 'नीति' किस तरह की धर्मनिरपेक्षता को स्कूलों में मजबूत करेगी! राज्य के एक कैबिनेट मंत्री अन्य छात्रों से सरेआम भेदभाव करते हुए मुस्लिम विद्यार्थियों के बीच छात्रवृत्ति का चेक वितरित कर रहे हैं। सरकार की यह घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में मध्यकालीन मानसिकता को बढ़ाने का काम करने जा रही है। (आजाद हिन्द, 17 अप्रैल, 2013)

राज्य के खिलाफ छात्र प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए [61]

- ममता की सरकार ने आगे यह भी घोषणा की कि लगभग 82 करोड़ रुपए ऋण के रूप में और 122 करोड़ पुस्तकालय के रूप में अल्पसंख्यक छात्रों को दिए जाएंगे। ये ऋण और पुरस्कार पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त कॉरपोरेशन (WBMDFC)[61] कलकत्ता के माध्यम से बांटे जायंगे।

58. Soudhriti Bhabani, "Mamta Bnaerjee's Minority Appeasement Draws Flak from Right, Left and Centre", India Today, Jan 28, 2016, http://indiatoday.intoday.in/story/mamata-banerjees-minority-appeasement-draws-flak-from-right-left-and-centre/1/581364.html (Accessed Feb. 15, 2017).
59. "Mamata's Allowance to Imams Unconstitutional, Rules Calcutta HC". Firstpost, Sept. 3, 2013, http://www.firstpost.com/politics/mamatas-allowance-to-imams-unconstitutional-rules-calcutta-hc-1080409.html (Accessed Feb. 11, 2017).
60. http://www.gettyimages.in/detail/news-photo/student-activists-of-akhil-bharatiya-vidyarthi-parishad-the-news-photo/181911912#student-activists-of-akhil-bharatiya-vidyarthi-parishad-the-student-picture-id181911912
61. "Mamta announces slew of sops for minorities", The Hindu, July 30, 2011, http://www.easternpanorama.in/index.php/music/155-2016/january-2016/3179-january-2016-politics-4 .(Accessed Feb. 26, 2017)

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राज्य महासचिव सिद्दीकुल्लाह चौधरी के साथ ममता बनर्जी

- वोट की निहित महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर, 2011 से ही ममता बनर्जी ने 40 लाख छात्रवृत्तियां (जिसकी कुल राशि 2350 करोड़ रुपए थी) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दीं। अल्पसंख्यक शिक्षा के कथित विकास के इस छद्म कदम के अलावा ममता ने 4.99 लाख का ऋण हर एक मुस्लिम युवा को बांटा। इस प्रक्रिया में कुल 880 करोड़ की राशि 2011 से अब तक वितरित की है। उनकी इस दोहरी नीति से विकास के नाम पर लगभग आधे बंगाल में अराजकता की आंधी उठने लगी है। पिछले 5 सालों में इस तरह के विकास से 3000 कब्रगाहों की दीवार को घेरा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण करना है।' पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास बोर्ड का गठन किया गया और राज्य के हर एक जिले में हज सेंटर की स्थापना की गई।

- पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ रही है तथा लगातार गैर-कानूनी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों का आगमन हो रहा है। इस तरह पश्चिम बंगाल उपरोक्त मुद्दों से जकड़ा हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वे रोजगार सृजन करने में नाकाम रही हैं दूसरी तरफ उसकी सरकार एक विशेष समुदाय के वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है।

- ममता बनर्जी 'निजी गृहा निजोभूमि प्रकल्प' योजना के अंतर्गत (जिसका उद्देश्य भूमिहीनों और गृहविहिनों को जमीन दान देने की है) भूमिहीन इमामों को भी भूमि अनुदान दे रही है ताकि अधिक से अधिक तुष्टीकरण किया जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगभग पांच हजार मकानों का निर्माण अल्पसंख्यकों के लिए करेगी और राज्य सरकार पचास हजार आवास अल्पसंख्यकों के लिए निर्मित करेगी।[62]

62. Ibid.

- ममता बनर्जी ने अपने शासन में कोई 'प्रगतिशील और सेक्युलर नीति' बनाने का प्रयास नहीं किया। वह 'जमीयत उलेमा-ए-हिन्द' के साथ गठजोड़ में शामिल है। वह इमामों को सब्सिडी दे रही है और बुर्का, शरीयत कोर्ट, हज को बढ़ावा दे रही है। ममता की यह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उनकी ऐसी तस्वीर पेश करती है कि उनकी सोच में कितना छिछलापन है।[63]

अहमद हसन इमरान के साथ ममता बनर्जी

- ममता अपने प्रशासन की गलतियों पर आंख बंद की हुई है। एक डाक्यूमेंटरी फिल्म (जो टीएमसी राज्यसभा सांसद अहमद हुसैन इमरान की है) यह साबित करती है कि 2013 में 24 साउथ परगना जिले में साम्प्रदायिक हिंसा में उनका हाथ था। इसके बावजूद ममता ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया। यह व्यक्ति स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) का संस्थापक सदस्य है।[64]

- तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से मुस्लिम चरमपंथी बिना किसी डर के राज्य की पुलिस और बीएसएफ को अपमानित कर रहे हैं। सबसे ऊपर सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी हाल में ही मुस्लिमों की भीड़ ने दो पुलिस जीपों को जब्त किया, पुलिस को मारा-पीटा

63. Upananda Bramachari, "Mamata Banerjee Nominates Rajya Sabha Seat In WB", Struggle For Hindu Existence, Jan. 22, 2014 , https://hinduexistence.org/2014/01/23/mamata-banerjee-nominates-a-hard-core-simi-man-and-fundamental-editor-for-a-rajya-sabha-seat-in-wb-tmc-is-too-dangerous-for-the-existence-of-hindus-in-west-bengal/html. (Accessed Feb. 28, 2017).
64. "Mamta Banerjee has West Bengal", Hindupost, Jan. 18, 2016, http://www.hindupost.in/news/mamta-banerjee-has-given-free-reign-to-islamists-in-west-bengal/ (Accessed Feb. 25, 2017).

और वीरभूम के मयूरेश्वर थाना को अपने नियंत्रण में ले लिया। जो भी बनर्जी सरकार की राजनीति के साथ नहीं चलेगा, उसे इसी तरह की कीमत चुकानी होगी। पिछले कई वर्षों से अनेक बार बीरभूम में पुलिस पर आक्रमण हुए हैं। इससे 2014 में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। बीरभूम जिले के पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के पुलिस मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा है क्योंकि आक्रमणकारियों को सरकार का पूरा समर्थन एवं सहयोग मिलता है।[65]

नगरपालिका मामलों के मंत्री बॉबी हकीम ने अपने निर्वाचित क्षेत्र को 'मिनी पाकिस्तान' वर्णित किया (डॉन, अप्रैल 29, 2016)

- पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है। यह जमीन बर्बादी की जमीन बन गई है। जहां पर जघन्य अपराधों में लिप्त जमाते इस्लामी के नेताओं और असामाजिक व्यक्तियों के सहयोग से बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार को गिराने की कोशिशें जारी हैं। यही लोग बंगाल को 'ग्रेटर बांग्लादेश' का भाग बनाना चाहते हैं।[66]

- एक दूसरी घटना में, एक मदरसा हेडमास्टर काज़ी मासूम अख्तर को इसलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वे अपने तल्पकुर आरा हाई मदरसे में मुस्लिम छात्रों को राष्ट्रगान सिखा रहे थे।[67]

काज़ी मासूम अख्तर

- ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे बढ़ चुकी है कि उन्होंने सरेआम 'कलिमा शहादत' गाना शुरू किया जो कि असल में इस्लाम अपनाने की प्रार्थना है। यह काम उन्होंने इमामों की उपस्थिति में किया। बनर्जी ने मेडिकल, टेक्नीकल, नर्सिंग स्कूल स्पेशल सब्सिडी के साथ मुसलमान छात्रों के लिए खोलने का वादा किया है।[68]

65. Ibid.
66. Ibid.
67. "Madrasa Headmaster Thrashed For Teaching His Students The National Anthem", Indiatvnews, Jan. 4, 2016, http://www.indiatvnews.com/news/india/madrasa-headmaster-beaten-up-for-national-anthem-56824.html. (Accessed Feb. 27, 2017).
68. Janet Levy, "The Muslim Takeover Of West Bengal", American thinker, Feb. 22, 2015, http://www.americanthinker.com/articles/2015/02/the_muslim_takeover_of_west_bengal. (Accessed Feb. 28, 2017).

ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में दंगे

ममता बनर्जी के शासन में हिन्दुओं के विरुद्ध साम्प्रदायिक दंगा राज्य प्रशासन के सहयोग से हुआ। सम्प्रदायवादियों के प्रति ममता की सहानुभूति ने असामाजिक तत्वों को भयमुक्त बना दिया है। उनके शासनकाल में साम्प्रदायिक हिंसा में वृद्धि होती गई है। ममता के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में लगभग 40 साम्प्रदायिक दंगे पश्चिम बंगाल में हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हिन्दू-मुसलमान के बीच में शत्रुता और साम्प्रदायिक झगड़ों एवं दंगों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अतिवादी मुस्लिमों के हिन्दुओं पर लगातार आक्रमण बढ़ रहे हैं। ये आक्रमण बिना किसी उकसावे के लगातार एक निश्चित उद्देश्य के साथ हो रहे हैं ताकि हिन्दुओं को घर से बेदखल किया जा सके और उनके जीविकोपार्जन को छीना जा सके।[69]

मौलवियों के साथ नमाज अदा करती हुई ममता बनर्जी[70]

69. Jaideep Mazumdar, " West Bengal is turning into communal tinder box, thanks to Mamta Banerjee" , Swarajya, Dec. 22, 2016, https://swarajyamag.com/politics/west-bengal-is-turning-into-a-communal-tinderbox-thanks-to-mamata-banerjee.(Accessed Feb. 21, 2017).
70. https://hinduexistence.files.wordpress.com/2012/04/what-is-in-her-islamic-mind.jpg.

ममता बनर्जी के शासनकाल में ये निम्नलिखित दंगे हाल में हुए हैं: :

धूलागढ़ के दंगे, 2016

एक साम्प्रदायिक दंगा हावड़ा के धूलागढ़ के एक गांव में दिसम्बर, 2016 में हुआ। जब मुस्लिमों ने ईद-ए-मिलाद के मौके पर लाउडस्पीकर के साथ एक जुलूस निकाला। यह जुलूस 13 दिसम्बर को पड़ने वाले मार्गशीर्ष पूर्णिमा के त्योहार को विफल करने के लिए किया गया जबकि प्रोफेट मोहम्मद का जन्मदिन 12 दिसम्बर को था।[71]

यह दंगा तब हुआ जब हिन्दुओं ने उस गांव में मुसलमानों से निवेदन किया कि जुलूस में लाउडस्पीकर के वाल्यूम को कम करें क्योंकि इससे पूजापाठ में दिक्कत हो रही है। इससे जुलूस में कुछ लोग भड़क गए और हिन्दुओं पर आक्रमण करने लगे। यह आक्रमण उनकी दुकानों और घरों पर भी हुआ। सरकार के अनुसार यह दंगा तीन-चार दिन तक चलता रहा। परिणामस्वरूप सैकड़ों घरों और दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।[72] डीएनए

धूलागढ़ दंगे

71. Ibid.
72. Swati Sengupta, "The Truth Behind The Riots In Bengal That The Media Doesn't Report", Huffington Post, Dec. 27, 2016, India. http://www.huffingtonpost.in/2016/12/26/ the-truth-behind-the-riots-in-bengal-that-the-media-doesnt-repo/. (Accessed Feb. 13, 2017).

समाचारपत्र की रिपोर्ट के अनुसार वहां के एक निवासी ने बताया कि अधिकतर हिन्दू अपने बच्चों के साथ भाग गए और जो बुजुर्ग घर में रह गए उनके मारने या डराने की नीयत से देसी बमों से उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया।[73]

जब इस संबंध में प्रश्न पूछा गया तो ममता बनर्जी मीडिया पर उखड़ गईं। राज्य सरकार ने पत्रकारों पर गैर-जमानती धाराएं लगाईं। ज़ी न्यूज चैनल के तीन कर्मचारियों को आई. पी.सी. की धारा 153 ए के तहत आरोपित किया।[74ए75] इस घटना में 150 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए।[76] जबकि हिन्दू लोग घर विहीन और पीड़ित रहे, लेकिन राज्य सरकार ने इस तरह की घटना के घटित होने पर अनभिज्ञता प्रकट की।

धूलागढ़ दंगों में निशाना बने घर (Image courtesy: Twitter/@Leopard212)

ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया के विपरीत घटना के पीड़ित भय में रहे। पीड़ितों ने बताया कि कैसे पुलिस मूकदर्शक बनी रही जबकि दंगाईयों ने उनके घरों को बर्बाद किया, उनकी सम्पत्ति को चुरा लिया। दंगों के पीड़ितों द्वारा आवाज उठाने के बावजूद कोई भी रक्षात्मक या प्रशासनिक सहायता कोलकाता से नहीं आई। यह कहना कठिन है कि प्रशासनिक विफलता किस कारण हुई क्योंकि वे लोग काफी समय से शांत रहे। पूरे गांव में अराजकता की स्थिति

73. "Dhulagarh Riots: West Bengal Town On The Boil After Communal Violence", Firstpost, Dec. 20, 2016, http://www.firstpost.com/india/dhulagarh-riots-west-bengaltown-on-the-boil-after-communal-violence-3177608.html. (Accessed Feb. 22, 2017).
74. Ibid.
75. "Mamata Banerjee Denies Riot In Dhulagarh, Blames Social Media", The Indian Express, Dec. 30 ,2016, http://indianexpress.com/article/india/mamata-banerjee-denies-riot-in-dhulagarh-blames-social-media-4451970/. (Accessed Feb. 19, 2017).
76. Animesh Pandey, "Dhulagarh Riots: Because When Hindus Are Killed, Riots Aren't Riots", RightLog.in, Dec. 22, 2016, http://www.thefrustratedindian.com/2016/12/mamata-burning-bengal-dhulagarh-riots/. (Accessed Feb. 26, 2017).

बन गई।[77] राज्य सरकार ने विपक्षी नेताओं एवं मीडिया को दंगा प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोक दिया क्योंकि यह माना गया कि उस क्षेत्र में मुसलमान आबादी की बहुलता को देखते हुए राज्य सरकार ने वोट बैंक के लिए कोई सख्त कानूनी कदम नहीं उठाया।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो धूलागढ़ घटना में शामिल थे। पीड़ितों को अनुग्रह राशि प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तकरीबन 35,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई।[78] लेकिन लगातार यह सवाल उठता है कि क्यों हिन्दू पीड़ितों को अनुग्रह राशि कम दी गई? यह भी सवाल उठा कि अगर कोई दंगा नहीं हुआ तो क्यों यह राशि दी गई? यदि राज्य की कार्यपालिका, प्रशासन और पुलिस उचित कार्रवाई करती तो इस स्तर की हिंसा से बचा जा सकता था।

कटवा के दंगे, 2016

कोलकाता से 165 किलोमीटर दूर कटवा एक शहर है जो बर्द्धमान जिले में स्थित है। यहां पर मुसलमानों की आबादी 22.72 प्रतिशत है।[79] गाय के मांस का टुकड़ा शनि महाराज मंदिर में फेंका गया तो कटवा में दिसम्बर में हिंसा शुरू हुई। जब गांव के लोग थाने में एफआईआर लिखवाने पहुंचे तो पुलिस ने यह कहते हुए एफआईआर लिखने से मना कर दिया कि यह विवाद उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बाद में एक आदिवासी व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया। हिन्दू जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। बंद सफल हो रहा था तभी प्रदर्शनकारियों पर एक मांस की दुकान से सुनियोजित हमला किया गया।[80] इस घटना से अनियंत्रित आक्रोश स्थानीय लोगों में फैला और हिंसा भड़की।

कटवा दंगों में जला घर

77. "BJP Team Stopped By WB Police From Entering Violence-Hit Area", PTI, Dec. 26, 2016, http://www.ptinews.com/news/8220521_BJP-team-stopped-by-WB-police-from-entering-violence-hit-area. (Accessed Feb. 26, 2017).
78. "Mob Chanting 'Pakistan Zindabad' Burnt My Home: Dhulagarh Riots Victim", Opindia.Com, Dec. 28, 2016, http://www.opindia.com/2016/12/mob-chanting-pakistan-zindabad-burnt-my-home-dhulagarh-riots-victim/. (Accessed Feb. 26, 2017).
79. Govt of India, "WBSMB : Population Details". Wbagrimarketingboard.Gov.In., 2017,http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.htm. (Accessed Feb. 26, 2017).
80. Upendra Bharti, "Islamists In Bengal Are Attacking Hindus", Struggle For Hindu Existence, Dec. 15, 2016, https://hinduexistence.org/2016/12/16/islamists-in-bengal-are-attacking-hindus-in-slightest-chance-courtesy-mamata-banerjee/ . (Accessed Feb. 26, 2017).

2016 में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध

मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन

ममता सरकार द्वारा मुस्लिमों को समर्थन के कारण पश्चिम बंगाल दमित हो चुका था। कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके परिणामस्वरुप हिन्दू त्योहारों के बीच में साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए। दुर्गा पूजा और मुहर्रम ताजिया के जुलूस के दौरान 11 और 12 अक्टूबर, 2016 को राज्य के 12 स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। माता दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान मुसलमानों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत मुहर्रम के जुलूस के जरिए दुर्गा पंडालों में हमला बोल दिया। कुछ ही समय में पंडाल में पटाखों और बम से हमला किया गया जिसके परिणामस्वरुप तलवार, कटारें, चाकू और लाठियां बाहर निकल आईं और हिन्दुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमला किया गया।[81]

इसका बीज तो ममता बनर्जी ने तब खुद ही बो दिया था जब उन्होंने दशमी और इस घटना के अगले दिन मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया। इस व्यवधान का केवल एक ही मुख्य कारण था वोट बैंक को लेकर उनकी गंदी राजनीति। अपनी इस गंदी राजनीति के चलते उन्होंने लोगों से अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करने का हक भी छीन लिया। क्योंकि विसर्जन का जुलूस और ताजिये का जुलूस का समय एक ही था और इसलिए वह चाहती थीं कि मूर्ति विसर्जन दशमी को 4 बजे से पहले हो जाये या फिर 2 दिन के बाद हो।

इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायलय ने दखल दिया और सरकार की आलोचना करते हुए कहा "राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट नजर आ रहा है कि वह अल्पसंख्यकों को ज्यादा मान दे रही है और जो लोग बहुमत में हैं उनके प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है.... राज्य सरकार एक समुदाय के पक्ष में कार्य कर रही है जो कि एक गैर-जिम्मेदाराना रवैया है और उन्होंने मां दुर्गा की पूजा कर रहे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है"। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि वह राजनीति और धर्म को एक साथ न मिलाए, लेकिन न्यायालय का हस्तक्षेप कहीं कोने में जा चुका था क्योंकि तब तक नुकसान तो हो ही चुका था! ममता बनर्जी के इस गलत निर्णय ने हिन्दुओं में भी गुस्सा भड़का दिया था। जिस वजह से 2 समुदायों के बीच में साम्प्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। जिसके परिणामस्वरूप हर जगह पर निकल रहे जुलूसों पर हमले हो रहे थे।[82]

81. "Atleast 12 Communal riots", Hindu Post, Oct. 14, 2016, http://www.hindupost.in/news/atleast-12-communal-riots-west-bengal-muharram-durga-puja-tensions/. (Accessed Feb. 23, 2017).
82. Jaideep Mazumdar, " West Bengal is turning into communal tinder box, thanks to Mamta Banerjee", Swarajya, Dec 22 ,2016, https://swarajyamag.com/politics/west-bengal-is-turning-into-a-communal-tinderbox-thanks-to-mamata-banerjee.(Accessed Feb. 21, 2017).

हाजीनगर के दंगे, 2016

हाजीनगर और हलिसहर पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना जिले की 2 नगरपालिकाएं हैं। इस चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 24.2 प्रतिशत है।[83] यहां के दंगों की कहानी अन्य दंगों की तरह ही है। यहां भी दंगें धार्मिक कार्यक्रम दुर्गा पूजा और मुहर्रम के बीच हुए। मामूली सा झगड़ा कब साम्प्रदायिक दंगों में बदल गया; किसी को पता ही नहीं चला। साम्प्रदायिक दंगे पूरे क्षेत्र में फैल गए। जिसके परिणामस्वरुप लगभग 30 घर और कई दुकानें जलकर राख हो गईं। 4 गाड़ियों को जला दिया गया और जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए। कई लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया गया। साम्प्रदायिक हमलों का कारण था- मुहर्रम के जुलूस में कम तीव्रता वाले बम का फेंका जाना और इस वजह से हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा फैलाई गयी। इस संघर्ष के कारण हिंसा छोटे से क्षेत्र से बढ़कर पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस हिंसा में हिन्दुओं के घरों-दुकानों और सम्पत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हिन्दुओं के प्रतिद्वंदियों ने इस बहस के आधार पर अपना बचाव किया कि ये दंगे सरकार द्वारा जारी किए दुर्गा मां की मूर्ति विसर्जन के प्रतिबंध का परिणाम था क्योंकि दोनों त्योहार एक ही दिन पड़े थे।[84] दंगों पर तृणमूल कांग्रेस की चुप्पी, राज्य की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निकम्मेपन के परिणामस्वरूप दोनों समुदायों में साम्प्रदायिक तत्वों में और बढ़ोतरी हो रही है।

हाजीनगर दंगे

83. Govt of India, "WBSMB : Population Details". Wbagrimarketingboard.Gov.In.2017, http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.htm. (Accessed Feb. 22, 2017).
84. Aniruddha Ghoshal, "Homes Ransacked In Communal Violence in Bengal, People Flee", The Indian Express, Oct. 17, 2016, http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/communal-clash-bengal-hazinagar-district-3086824/html. (Accessed Feb. 20, 2017).

इलम बाजार के दंगे, 2016

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के इलम बाजार क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 45 फीसदी है।[85] मार्च, 2016 में जब एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया उस समय इलम बाजार क्षेत्र से एक व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी। उस व्यक्ति को उसके इस कृत्य के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उस आरोपी को पुलिस स्टेशन से रिहा कराने के लिए लूटमारी की गई और पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई।[86]

इलम बाजार पुलिस थाना

उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मजबूरन पुलिसकर्मियों को उनके विरूद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तब पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस और जनता की गाड़ियों को हानि पहुंचाने के अलावा उपद्रवियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-60 पर भी जाम लगा दिया। पुलिस के अनुसार अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाई गई थी और रिजुआल इस्लाम नाम के एक प्रदर्शनकारी के सिर पर गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।[87] यह प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने में भी शामिल था। अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में ममता बनर्जी ने पुलिस द्वारा किए गए हमले की आलोचना की और आम जनता के दिमाग में डर बैठा दिया। क्या उनके इस कृत्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिए? इस प्रकार के बड़े दंगे प्रशासन की नाकामी और राज्य सरकार की सत्ता और वोट के प्रति तीव्र लालसा

85 . Govt of India, "WBSMB : Population Details".,Wbagrimarketingboard.Gov.In, 2017, http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.htm (Accessed Feb. 19, 2017).

86. Ayub Dawood, "Facebook Post over……...Match", Scoopwhoop, March 3, 2016, https://www.scoopwhoop.com/One-Killed-As-Mob-Clashes-With-Police-In-West-Bengals-Birbhum-Over-Facebook-Post/#.czboa76hg. (Accessed Feb. 23, 2017).

87. Sanjay Pandey, "After Malda....Illumbazar", FirstPost, March 4, 2016, http://www.firstpost.com/india/after-malda-now-illambazar-why-police-are-a-soft-target-in-mamata-banerjees-bengal-2656932.html. (Accessed Feb. 25, 2017).

के कारण भड़के थे। क्या उन्होनें पीछे घटी हिंसा के मामले को पूरी दृढ़ता और शीघ्रता से निपटाया? अगर ऐसा होता तो इस प्रकार के खतरनाक हमले बार-बार नहीं दोहराए जाते।[88]

कलियाचक (मालदा) के दंगे, 2016

कलियाचक (मालदा) हिंसा से पश्चिम बंगाल में इस्लामीकरण की काफी बड़ी तस्वीर सामने आई है। 3 जनवरी, 2016 में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक में दंगे काफी उग्र रूप ले चुके थे। इस क्षेत्र में 89 फीसदी मुस्लिम आबादी है।[89] कलियाचक में दिसम्बर 2015 के आखिरी सप्ताह में उस समय विद्रोह की ज्वाला धधक उठी जब कमलेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने मोहम्मद पैगम्बर को समलैंगिक कहते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी।

कलियाचक दंगों के दौरान लगी आग

इस्लामिक कट्टरपंथियों के एक इशारे पर 3 जनवरी, 2016 को कलियाचक टैक्सी स्टैंड पर हजारों की संख्या में मुसलमान एकत्रित हो गए। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने भीड़ को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण देने शुरू किए। शीघ्र ही मुसलमानों की उग्र भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया जिसके बाद हिंसक वारदातें बढ़ती चली गईं। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सम्पत्ति, बीएसएफ और सार्वजनिक वाहनों पर अपनी बर्बरता दिखानी शुरू की। इतना ही नहीं; इन प्रदर्शनकारियों ने कलियाचक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिससे वहां के 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए।[90]

ये मुसलमान उपद्रवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने हिन्दुओं की सम्पत्ति को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने हिंदुओं के घरों, दुकानों पर हमला कर उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया। उनके सामान की लूटपाट की। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हिन्दू महिलाओं का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया।

88. Ibid.
89. Govt of India,"WBSMB : Population Details". Wbagrimarketingboard.Gov.In.2017, http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.htm. (Accessed Feb. 17, 2017).
90. Soudhriti Bhabani, "48 hours after riots", India Today, Jan. 6, 2016, http://indiatoday.intoday.in/story/kaliachak-in-malda-turns-ghost-town-48-hrs-after-violence/1/563443.html (Accessed Feb. 28, 2017).

3 जनवरी, 2016 को मालदा में हुए दंगे के दौरान उन्मादी भीड़ आगजनी करते हुए

मालदा दंगों के बाद की तस्वीर

पूरे क्षेत्र में कई घंटों तक अराजकता व्याप्त थी। इस हालात को देखते हुए जिला मुख्यालय ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल को भी पूरे क्षेत्र में तैनात कर दिया। इतने बड़े स्तर पर हमला होने के बाद भी ममता बनर्जी ने उन दिनों चुप्पी साध रखी थी।

पश्चिम बंगाल में दंगों की ज्वाला भड़की हुई थी और इसके बावजूद सारी सड़कों पर इस्लाम जिन्दाबाद, नारा-ए-तकबीर, कमलेश तिवारी को फांसी दो जैसे नारे नज़र आ रहे थे। राज्य सरकार के अनुसार यह घटना साम्प्रदायिकता से जुड़ी हुई नहीं थी। आनंदबाजार पत्रिका ने पूरी घटना को छापा था और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हिंसा के 24 घंटे बाद भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आपसी संघर्ष के कारण पूरा शहर चुप्पी साधे हुए था।[91]

जब बात वोट बैंक की राजनीति पर आती है तो ममता बनर्जी उससे बेदाग बच निकलती हैं। वह नोटबंदी से परेशान गरीबों की मदद कर स्वयं को दूरदर्शी कहलाना तो पसंद करती हैं लेकिन उनके मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जब उनके समर्थकों ने मारपीट और लूटपाट की तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं।

नादिया के दंगे, 2015

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज ब्लॉक में हुए साम्प्रदायिक दंगों ने काफी उग्र रूप ले लिया था। इस जिले की पूरी आबादी का 25.5 फीसदी मुस्लिम आबादी है। कालीगंज पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले दो गांव नादिया और जुरानपुर के हिन्दू और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक

91. "Why did Media ....riots", Scroll.in, Jan. 6, 2016, https://scroll.in/article/801459/it-was-localised-violence-in-a-crime-prone-area-why-some-newspapers-were-low-key-on-the-malda-violence. (Accessed Feb. 25, 2017).

दंगे भड़के और इसके परिणामस्वरूप वहां चार लोग मारे गए और आठ घायल हो गए। इस साम्प्रदायिक तनाव का कारण था; नादिया जिले के जुरानपुर गांव में जुलूस पर हमला। यह हमला उस समय हुआ जब हिंदू संप्रदाय के लोग धर्मराज मेले के वार्षिक आयोजन का पारंपरिक उत्सव की तरह आनंद ले रहे थे। शाम करीब 3 बजे के आसपास जब हिंदू श्रद्धालु जुरानपुर मस्जिद की तरफ से घर वापस जा रहे थे, तभी तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में मुसलमान उपद्रवियों के हुजूम ने जुलूस पर हमला बोल दिया। इसके बाद दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला बोल दिया, यहां तक कि एक दूसरे पर बम भी फेंके गए। चश्मदीद बताते हैं कि दंगों को रोकने के लिए पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। पश्चिम बंगाल के राज्य प्रशासन ने इस बारे में कुछ भी कहने की ज़हमत नहीं उठाई। तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा की तरह साम्प्रदायिक सद्भावना का हवाला देते हुए चुप्पी साध रखी थी। कुछ को छोड़कर प्रमुख बंगाली मीडिया संस्थानों ने इसे अखबारों की खबर नहीं बनने दिया। इस ग्राड्यंत्र भरी चुप्पी का अपना ही एक अतीत है।[92]

उस्थि के दंगे, 2015

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के उस्थि गांव में भी दंगे भड़क उठे। इस तहसील की पूरी आबादी में से 56 फीसदी आबादी मुसलमानों की है।[93] जनवरी, 2015 में पश्चिम बंगाल के उस्थि पुलिस थाना, मंदिर बाजार पुलिस थाना और डायमंड हार्बर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर बंगाली हिंदुओं पर हमले किए गए।[94] मुस्लिम उपद्रवियों ने हिंदुओं का शोषण किया, उनके घर और दुकानों में लूटपाट की। ऐसा कहा जाता है कि यह सब अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री गियासुद्दीन मोल्ला की उपस्थिति में हुआ और वे हिन्दू विरोधी गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुसलमानों को मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर्स् से इस दंगें में शामिल होने के लिए भड़काया जा रहा था।

पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री गियासुद्दीन मोल्ला इस प्रकार की तबाही के जिम्मेदार थे क्योंकि कथित तौर वे स्वयं ही अपने गुंड़ों के साथ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की चौकसी कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम आबादी वाले उस गांव में पुलिस को जाने से रोका जहां असामाजिक तत्व पहले से ही घुसपैठ कर चुके थे। पुलिस भी राज्य सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी और उन्होंने बिना सोचे-समझे हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।[95]

92. "5 killed...injured", Struggle For Hindu Existence, May 5, 2015, https://hinduexistence.org/2015/05/05/5-killed-over-8-injured-in-communal-clashes-in-nadia-district-west-bengal/html (Accessed Feb. 23, 2017).
93. Abhi Mitra, "Muslims Vandalized Hindu Areas And Business At Usthi In West Bengal With The Help Of State Minister", Bengalspotlight, Jan. 29, 2015, http://bengalspotlight.blogspot.in/2015/01/muslims-vandalized-hindu-areas-and.html.(Accessed Feb. 23, 2017).
94. Govt of India, "WBSMB : Population Details". Wbagrimarketingboard.Gov.In. 2017 http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.htm (Accessed Feb. 18, 2017).
95. Saswati Sarkar, "Ban on Durga puja", Bengalspotlight, Nov. 27, 2015, http://bengalspotlight.blogspot.in/2015/01/muslims-vandalized-hindu-areas-and.html (Accessed Feb. 28, 2017).

बर्दवान बम ब्लास्ट, 2014

बर्दवान बम धमाके के बाद की तस्वीर

अक्टूबर, 2014 में पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के खागरागढ़ इलाके की एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ। इस इलाके की मुस्लिम आबादी 20 फीसदी से अधिक थी।[96] यह बिल्डिंग तृणमूल कांग्रेस के नेता नुरुल हसन चौधरी की थी। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय था। जब पुलिस अधिकारी उस स्थान पर पहुंचे तब दो महिलाओं ने उन्हें अंदर घुसने से रोका इसके साथ ही उन महिलाओं ने उस बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी भी दी। उन महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों को काफी देर तक अंदर आने से रोके रखा; जिससे वहां पर रखे हुए बहुत से दस्तावेज और सबूत जल जाएं और पुलिस के हाथ कुछ भी न लगे। जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया तब उनके पास से 55 'तत्कालिक विस्फोटक उपकरण' (आई. ई. डी.) के साथ घड़ी के डायल, सिम कार्ड और टूल्स मिले थे जिनका इस्तेमाल विस्फोटक उपकरण तैयार करने में किया जाता था। सुरक्षा एजेंसियों का पूर्वानुमान था कि कुछ ही दिनों में तत्कालिक विस्फोटक उपकरण (आई. ई. डी.) से भारत के किसी शहर में धमाके करने की योजना थी।[97] इतना ही नहीं, उस स्थान से तालिबान प्रशिक्षण की वीडियो, मानचित्र, साम्प्रदायिक प्रचार वाली अरबी किताबें भी मिली थीं। ममता बनर्जी ने इसमें भी आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति बरकरार रखी। उन्होंने कहा "केंद्र ने पहले कहा था कि अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को बाहर निकाला जाना चाहिए।[98]

96. Govt of India, "WBSMB : Population Details". Wbagrimarketingboard.Gov.In. 2017, http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.html. (Accessed Feb. 26, 2017).
97. Debajyoti Chakroborty, "IM men killed making IEDs", TOI, Oct. 5, 2014, http://timesofindia.indiatimes.com/india/IM-men-killed-making-IEDs-in-Trinamool-leaders-house/articleshow/44369811.cms. (Accessed Feb. 26, 2017).
98. "Burdwanblastcase", TOI, Nov. 26, 2014, http://timesofindia.indiatimes.com/india/Burdwan-blast-case-Mamata-Banerjee-sniffs-plot-her-cops-claim-NIAs-terror-reward/articleshow/45278274.cms (Accessed Feb. 24, 2017)

कैनिंग के दंगे, 2013

कैनिंग में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक इमाम की हत्या के बाद हिंदुओं पर हिंसा

कैनिंग पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का मुख्यालय है। पूरे जिले की आबादी की 62 फीसदी मुस्लिम आबादी इस कस्बे में रहती है।[99] फरवरी, 2013 में एक इमाम अपने सहयोगियों के साथ जामलता के धार्मिक अनुष्ठान से लौटा रहा था। आधी रात में नलियाखली में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौलवी से 1,150,000 रुपए कैश लूटे गए और बाद में गोली मार दी गई। जैसे ही इमाम की मौत की खबर फैली, हजारों की संख्या में शोक में डूबे हुए मुसलमानों ने उनके शव को घेर लिया और उन पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों पर हमला कर दिया जो शव को लेने गए थे। इसके बाद तो उपद्रवियों ने अल्लाह-हु अकबर के उद्घोष के साथ पड़ोस के गांवों में 200 से ऊपर हिंदुओं के घर लूटे और जलाए[100] सैंकड़ो मंदिरों और भगवान की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। नलियाखली, हेरोभंगा, गोपालपुर और गोलाडोगरा में खौफ इस कदर फैल गया था कि 2000 से भी अधिक लोगों ने गांव छोड़ दिया। हिंसा की घटना की सूचना कैनिंग, जयनगर, कुलताली और बसंती पुलिस थाना क्षेत्र से आ रही थीं। संयोजकों ने व्यवस्थित रूप से हिंदू समुदाय पर यह हमला किया था लेकिन इस पर ममता बनर्जी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। उन्होंने केवल शांति की अपील की और हत्या के मामले में विशेष जांच का आश्वासन दिया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी।[101]

99. Govt of India, "WBSMB : Population Details". Wbagrimarketingboard.Gov.In.2017 http://www.wbagrimarketingboard.gov.in/MinorityPopulation/Population_murshidabad.htm. (Accessed Feb. 25, 2017).
100 Janet Levy, "The Muslim Takeover Of West Bengal", Americanthinker, Feb. 22, 2015, http://www.americanthinker.com/articles/2015/02/the_muslim_takeover_of_west_bengal.html. (Accessed Feb. 28, 2017).
101. "BJP Urges didi …silence", Indian Express, Dec. 28, 2016, http://gulfnews.com/news/asia/india/communal-violence-returns-to-haunt-bengal-1.1150036. (Accessed Feb. 24, 2017).

इन राजनीतिक चालबाजियों के चलते साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की आवाज अनसुनी कर दी गई। ऐसे जिलों की आबादी डर के साए में जी रही थी। सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार उनसे छिन चुका था। उन्हें कहीं से भी न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। क्या फायदा ऐसे लोकतंत्र का जब समाज के हिंसक तत्वों के कारण वहां के नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? ममता बनर्जी नहीं चाहती थीं कि उनका प्रशासन मुस्लिम दंगाईयों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिन सकता है और उनके हाथ से बंगाल की सत्ता जा सकती है।

पश्चिम बंगाल में प्रशासन की नाकामी

तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 2011 में बंगाल में नए युग की आशा का संचार हुआ था। ममता बनर्जी ने लोगों से परिवर्तन लाने का वादा किया लेकिन वहां के लोगों को निराशा ही हाथ लगी। ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने विकास और तरक्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ममता बनर्जी की वोट बैंक के लिए जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी उससे संवैधानिक तंत्र पूर्ण रूप से टूट चुका था। लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने के लिए ममता बनर्जी ने राजनीति के प्रमुख हथियार 'आतंक और षडयंत्र' का इस्तेमाल किया।

साम्प्रदायिक आक्रमकता और संघर्ष केवल एक ओर इशारा कर रहे थे। प्रशासन लोगों की जान और सम्पत्ति दोनों को बचाने में असफल हो गया। संविधान स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर गर्व महसूस करता है लेकिन देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो एक सम्प्रदाय-विशेष के साथ ही धर्मनिरपेक्षता दिखाते हैं। उन्होंने देश को दो गुटों- बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांटकर रख दिया है। अपने राजनीतिक मुद्दों के कारण धर्मनिरपेक्षता के लिए एक नई परिभाषा गढ़ दी है। यही कारण है कि राजनीतिक प्रवचनों के चलते धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा ने अपना मूल तत्व और प्रतीकात्मकता को खो दिया है।[102]

राज्यतंत्र और संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? यह कमजोर की शक्तिशाली से रक्षा करने के लिए बनाया जाता है और अगर राज्य ऐसा करने में असफल होता है या किसी शक्तिशाली के हाथों की कठपुतली बन जाता है, तो वह इसका जिम्मेदार संविधान द्वारा उसे दी गई शक्ति को ठहराता है। दंगों के दौरान तृणमूल कांग्रेस की चुप्पी ने साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दिया। कुछ जगह प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करने का प्रयास किया लेकिन सरकार ने इस प्रकार के दंगों से इनकार किया। यह द्विभाषी 'ओवेलियन अवधारणा' के समान है।

ऐसा लगता है जैसे मीडिया को वहां के बारे में कुछ भी छापने के लिए डराया जाता रहा है। लोकतंत्र उनकी इस तरह की हरकतों की निंदा करता है। राज्य सरकार द्वारा मीडिया को प्रतिबंधित करने की घोर निंदा कई मंचों से की गई है।

102. Ajoy Mahaprashasta, "Communal Rioting Lays Bare Volatile Political Ground In Bengal", The Wire, Oct. 20, 2016, https://thewire.in/74385/communal-rioting-lays-bare-volatile-political-ground-in-bengal/html. (Accessed Feb. 26, 2017).